04 - समुद्री व्यापार, बीमा संकट और भारत की चुनौतियाँ

05 - समानता से हासिल होगा सशक्तिकरण

06 - देवास में जल गंगा संवर्धन अभियान: बावड़ी सफाई, रैली और...

07 - लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मामलों का हो समय...

सुबह सवेरे

A Daily News Magazine

भोपाल

शनिवार, 25 अप्रैल, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 232, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

आज फूलों पर
अंगारे
दहक रहे हैं

आज नदियां
मगरमच्छों से
भरी हुई है

आज धरती का
सौंदर्य
रसातल जा रहा है
आज चारों ओर
यमदूत
भटक रहे हैं
आज हर साँस पर
बंदिशें
लगी हुईं हैं।

- दुर्गाप्रसाद झाला

प्रसंगवश

पश्चिम बंगाल में ममता बनाम अमित शाह की जंग

उमेश चतुर्वेदी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लड़ाका है। धूल से उठकर राजनीतिक आसमान का तारा अगर वे बनी हुई हैं, उसकी वजह उनका संघर्षशील व्यक्तित्व ही है। लेकिन कोलकाता के मैदान में इस बार यह योद्धा फंसा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह उनसे दो-दो हाथ कर रही है, निश्चित तौर पर उसके पीछे नरेंद्र मोदी की अगुआई में बंगाल की धूल में लगातार परिश्रम कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आज अगर बंगाली की सियासी लड़ाई आर-पार के दौर में आ चुकी है तो इसके पीछे अमित शाह की रणनीति काम कर रही है।

साल 2021 के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद कहा गया था कि बीजेपी चुनाव जीतते-जीतते हार गई है। ममता का संघर्ष बीजेपी की रणनीतियों पर भारी पड़ गया था। पांच साल बाद कोलकाता के रायटर्स बिल्डिंग पर कब्जे को लेकर सेनाएं सज गई हैं। लेकिन इस बार हालात बदले नजर आ रहे हैं। इसकी वजह अमित शाह का चुनाव प्रचार की कमान खुद संभालना है, जिन्होंने 170 सीटें जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर रखा है। पिछले विधानसभा चुनाव में पिछड़ने के बावजूद अमित शाह ने राज्य की यात्राएं जारी रखीं और इसके जरिए अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित बनाए रखा। इस बार बीजेपी अगर सत्ता की प्रबल दावेदार के रूप में उभरी है तो इसकी बड़ी वजह बूथ प्रबंधन तो है ही, घुसपैठ और महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाना भी है। बंगाल के बारे में कहा जाता है कि वह जो आज सोचता है, पूरा देश उस पर बाद में आगे बढ़ता है। शक्ति पूजा की संस्कृति वाले राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता के राज में कई बार सवाल उठे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज में रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और बर्बर हत्या के बाद अंग्रेजों की पहली राजधानी का भद्रलोक उद्वेलित हो उठा। अभी इसकी आंच ठंडी पड़ी नहीं कि कस्बा लॉ कालेज की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ। इसके पहले संदेशखाली में हुई कथित तौर पर यौन हिंसा और ज़मीन हड़पने के मामलों से पश्चिम बंगाल का समाज उद्वेलित रहा। अमित शाह के बार-बार के बंगाल दौरे के चलते बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा के मसले को कभी धीमा नहीं पड़ने दिया। इन्हीं वजहों से महिला सुरक्षा को लेकर तृणमूल कांग्रेस सवालों के घेरे में आ गई। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट भी राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की ही तसदीक करती है, जिसके अनुसार, राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 34,691 मामले दर्ज किए गए और एसिड हमलों में इसका हिस्सा सबसे ज़्यादा करीब 27.5 प्रतिशत रहा। बीजेपी को महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाने में ममता बनर्जी के एक बयान से भी मिला, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं को शाम सात बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। बीजेपी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आरजी कर की पीड़िता की मां मंजू देवनाथ को पनियाहाटा से उम्मीदवार बनाकर एक तरह से राज्य की महिलाओं को संदेश दे दिया है, संदेश यह कि वह उनकी सुरक्षा के लिए संजीदा है। बीजेपी ने महिलाओं को लुभाने के लिए दुर्गा सुरक्षा दस्ते बनाने और नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देने का भी वादा किया है। इसके साथ ही महिलाओं को मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह प्रतिमाह तीन हजार रूपए देने का वादा किया है। यहां याद रखना चाहिए कि ममता सरकार हर महीने महिलाओं को डेढ़ हजार रूपए दे रही है।

साल 2021 में राज्य में तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटें और करीब 44 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 38 प्रतिशत वोट के साथ 77 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। हालांकि 2016 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले देखें तो पार्टी ने तीन सीट और करीब 28 प्रतिशत वोट की तुलना में बड़ी छलांग लगाई। अमित शाह ने इसी बुनियाद को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की रणनीति बनाई। इसके तहत उन्होंने दो बातों पर जोर दिया। उन्होंने उन गढ़ों को और मज़बूत बनाने की रणनीति बनाई, जहां पहले से ही पार्टी मजबूत स्थिति में है। इसके साथ ही उन चुनाव क्षेत्रों में आधार बढ़ाने की कोशिश तेज की, जहां 2021 में वह बहुत कम अंतर से हारी थी। इसके साथ ही अमित शाह ने पार्टी के भीतर की गुटबाज़ी को भी सुलझाने की कोशिश की। राज्य में पार्टी के अध्यक्ष रहे दिलीप घोष के बारे में माना जा रहा था कि वे नाखुश हैं। अमित शाह ने उनसे मुलाकात करके तृणमूल से आए शुभेंदु अधिकारी से बीच उनके मतभेदों को दूर करने की कोशिश की।

ममता बनर्जी ने पिछली बार बंगाली माटी और मानुष यानी स्थानीय को मुद्दा बनाया था। उन्हें इस मुद्दे से पिछली बार मदद भी मिली। इस बार भी ममता विपक्ष यानी बीजेपी के नेताओं के बाहरी होने का आरोप लगा रही हैं। इसके जवाब स्वरूप अमित शाह ने ऐलान किया है कि अगर पश्चिम बंगाल में पार्टी सत्ता में आई तो राज्य का मुख्यमंत्री 'धरती का बेटा' यानी स्थानीय व्यक्ति ही बनेगा। पार्टी ने इस बार घुसपैठ को भी बड़ा मुद्दा बनाया है। राज्य में विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान राज्य में नब्बे लाख वोटरों के नाम हटाने को लेकर ना सिर्फ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समेत समूचा गैर बीजेपी दल मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि अमित शाह चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के कदम को सही बताया है। बीजेपी ने वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आई तो राज्य से अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर करेगी। इसके साथ ही पार्टी ने सत्ता में आने के पैंतालीस दिनों के अंदर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए केंद्र सरकार को जमीन देगी। बीजेपी ने इसके जरिए बांग्लादेश की ओर हो रही पशु तस्करी को रोकने का भी ऐलान किया है।

राज्य में भ्रष्टाचार को भी बड़ा मुद्दा बनाने मंआ बीजेपी कामयाब रही है। यहां के भर्ती घोटाले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 26 हजार नौकरियां रद्द कर दी थी। इसके साथ ही राशन और मिड-डे मील, मनरेगा जॉब कार्ड घोटाला भी सुर्खियां बनता रहा है। बीजेपी ने इस बार इसे भी मुद्दा बनाया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इसे केंद्र की बदले की कार्रवाई बताती रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। सही तौर पर कहें तो इस बार मुकाबला ममता बनाम अमित शाह है। इस जंग में अमित शाह सफल होंगे या ममता एक बार फिर उन्हें मात देने में कामयाब रहेंगी, यह तो चार मई को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा।

5 तारीख के बाद अंग, बंग और कलिंग में बीजेपी

अमित शाह का बड़ा दावा-तीनों जगह भाजपा का शासन होगा

कोलकाता (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे लिए पूरा बंगाल ही टफ था। कई राज्यों में हम सीधे जीत हासिल करते हैं, लेकिन यहां हम 77 सीटों पर हैं। सरकारें देश की जनता बनाती हैं, इसलिए यहां भी भाजपा सरकार का बनना तय है। मुझे

- **कहा-अगला सीएम यहीं का होगा, बस दीदी का भतीजा नहीं होगा**

तो बीजेपी की सुनामी दिख रही है। बड़े अंतर से सीटें बढ़ेंगी। मध्यमग्राम में हुए रोड शो में जो नजारा मैंने देखा, वह मेरी कल्पना से भी कहीं बड़ा था। पहले कोलकाता शहर में कांग्रेस को वोट मिलता था, फिर कम्युनिस्टों को, उसके बाद ममता बनर्जी को। अब भाजपा आएगी और 30 साल तक रहेगी। यहां एंटी इंकम्बेंसी लहर चरम पर है।

पूर्वोदय की यात्रा मोदी जी ने शुरू की है वह आगे बढ़ेगी

अमित शाह ने कहा, एक बहुत बड़ी आशंका बताई जाती थी कि जनसमर्थन तो है, लेकिन वह पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेगा क्या। अब यह दूर हो गई है। दूसरे चरण के लोगों की जिम्मेदारी है कि बदलाव के दौर का वे आगे बढ़ाएं। 5 तारीख के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह भाजपा का शासन होगा। मोदी जी ने 2014 में कहा था भारत माता की दोनों भुजाओं को सम विकास होना चाहिए। पूर्व के क्षेत्र किसी न किसी कारण से पिछड़े हैं। भाजपा के शासन के आने बाद जो पूर्वोदय की यात्रा मोदी जी ने शुरू की है वह आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं भाजपा का शासन आया तो बंगाल के लोग बाहर कर दिए जाएंगे। मैं दीदी को बताना चाहूंगा कि अगला सीएम बंगाल का ही होगा। वह सिर्फ आपका भतीजा नहीं होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। हमारी प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा है।

बंगाल में 'भतीजा टैक्स' खत्म करेंगे

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद व्यापारियों को किसी तरह का 'भतीजा टैक्स' या 'भाइपो टैक्स' नहीं देना पड़ेगा। हम सिंडिकेट व्यवस्था को खत्म करेंगे। जो प्रशासन राजनीतिक और आपराधिक हो गया है, वह एक तरह का दानव बन चुका है। हम बंगाल के लोगों को इस दानव से मुक्त कराएंगे। अमित शाह ने कहा, हम असम की तर्ज पर बंगाल में भी अनाधिकृत कब्जों पर ड्राइव चलाकर उन्हें मुक्त कराने का काम करेंगे। यहां धार्मिक उत्सवों पर हमलों की परंपरा रही है। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई इन पर हमला न कर पाए। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकसित भारत की यात्रा में जुड़ चुका है। आपका प्यार पहले चरण में दिखाई दिया है। आपका यह उत्साह दूसरे चरण में भी दिखाई देगा, यह उम्मीद करता हूं। पुराने चुनाव भूल जाइए आने वाले भविष्य के लिए मतदान करें और बीजेपी की सरकार बनाएं।

मणिपुर में सड़क पर उतरीं मेड़रा पाईबी की महिलाएं

- **दिन में रास्ते रोक कर धरना, रात में मशाल रैलियों से कानून-व्यवस्था संभाल रहीं**

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर में बीते 7 अप्रैल को रॉकेट हमले में दो बच्चों की मौत हो गई थी। प्रदर्शनों में 3 मौतें हो गई थीं। तबसे विरोध-प्रदर्शन चल रहे हैं। अशांति के बीच 18 अप्रैल से पूर्ण बंद लागू है। सामान्य जीवन ठप है। इसी बीच अब मेइरा पाइबी समूह की महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। हजारों महिलाओं का यह समूह शांति-व्यवस्था के लिए न केवल सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि सामाजिक स्तर पर लोगों को भी जोड़ रहा है। ये महिलाएं दिन में रास्ते रोक रही हैं, धरना दे रही हैं। वहां से न पुलिस निकल सकती है, न कोई और। वहीं, रात में मशाल रैलियों से इलाकों की पहरेदारी भी कर रही हैं।

जिला स्तर पर कार्यक्रमों में होगा आदर्श पशुपालकों का सम्मान

प्रदेश में सहकार से हो रहा है डेयरी गतिविधियों का विस्तार : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दुग्ध उत्पादन से जुड़ी गतिविधियां किसानों की आय बढ़ाने में प्रभावी रूप से सहायक है। किसानों की आय दोगुना करने के लिए किसान कल्याण वर्ष में राज्य सरकार डेयरी गतिविधियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश के दुग्ध संघों को दिए जा रहे सहयोग से दुग्ध संकलन में वृद्धि हुई है और किसानों को भी दूध के बेहतर दाम मिल रहे हैं। सहकार के भाव से डेयरी गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है। दुग्ध समितियों में महिला सदस्यता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। डेयरी सहकारी कवरेज के विस्तार और सुदृढ़ीकरण, नई डेयरी प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण और पशु चारा संयंत्र के आधुनिकीकरण, डेयरी वैल्यू चैन के डिजीट्लाइजेशन, पारदर्शिता और दुग्ध उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए कार्ययोजना बनाई जाए। डेयरी विकास योजना के अंतर्गत 26 हजार गांवो को जोड़ने, प्रतिदिन दुग्ध संकलन 52 लाख किलोग्राम तक करने का लक्ष्य रख, गतिविधियां संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ये निर्देश मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की राज्य स्तरीय संचालन समिति की द्वितीय बैठक में दिए।

मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में हुई बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री लखन पटेल, वरिष्ठ विधायक तथा वरिष्ठ विधायक एवं अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन तथा अध्यक्ष नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड श्री मीनेष शाह उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध क्षेत्र में अनुभव का लाभ राजधानी से लेकर ग्राम स्तर तक सुनिश्चित किया जाए। दूध और दुग्ध उत्पादों के बिक्री में सुधार के लिए ब्राण्ड सुदृढ़ीकरण और नई पैकेजिंग डिजाइन कर उत्पादों की पहुंच का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दुग्ध उत्पादन में वद्धि और विभिन्न दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए किसानों को नवाचार करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों तथा प्रदेश के युवाओं को डेयरी टेक्नोलॉजी की नई तकनीकों से परिचित कराने की भी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आदर्श पशुपालकों को सम्मानित करने, दूधारू पशुओं की प्रदर्शनी आयोजित करने और डेयरी के संबंध में सूचना सम्प्रेषण के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और दुग्ध संघों का कार्यअनुबंध करने के बाद वर्ष 2025-26 में 1752 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया तथा 701 निष्क्रिय दुग्ध समितियों को क्रियाशील किया गया। प्रदेश में प्रतिदिन 9 लाख 67 हजार कि.ग्रा. दुग्ध संकलन किया जा रहा है, साथ ही 153 नवीन बल्क मिल्क कूलर की स्थापना की गई है। दूध और दूध उत्पादों का क्रेडिट पर विक्रय बन्द कर दिया गया है।

क्या 'आप' भी एक आम सियासी पार्टी बनने की राह पर है?

हेमंत पाल

लेखक 'सुबह सवेरे' के स्थानीय संपादक है।

भारतीय राजनीति में 2010 के दशक की शुरुआत एक बड़े बदलाव की उम्मीद लेकर आई थी। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली एक नई राजनीतिक शक्ति अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनी 'आम आदमी पार्टी' (आप) ने न केवल पारंपरिक राजनीति को चुनौती दी, बल्कि शासन के नए मॉडल का वादा भी किया। शुरुआती दौर में यह पार्टी एक आंदोलन की तरह दिखी, जिसमें वैचारिक विविधता, पारदर्शिता और जनभागीदारी प्रमुख तत्व थे। लेकिन, समय के साथ यह सवाल उठने लगा कि क्या यह पार्टी भी उसी केंद्रीकृत नेतृत्व और राजनीतिक महत्वाकांक्षा का शिकार हो गई, जिसके खिलाफ यह खड़ी हुई थी।

आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय इसके साथ कई ऐसे चेहरे जुड़े, जिनकी अपनी अलग विश्वसनीयता और पहचान थी। अन्ना हज़ारे के आंदोलन से प्रेरित यह पार्टी एक नैतिक राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरी। इसके संस्थापकों में प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव जैसे नाम शामिल थे। इन नेताओं की उपस्थिति ने पार्टी को बौद्धिक मजबूती और वैचारिक गहराई दी। ऐसा लगा कि 'आप' केवल चुनाव जीतने की मशीन नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत है। लेकिन, यही विविधता आगे चलकर आंतरिक टकराव का कारण भी बनी।

समय के साथ पार्टी के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे। योगेश यादव और प्रशांत भूषण जैसे नेताओं का पार्टी से अलग होना केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं था, बल्कि यह संगठन के भीतर लोकतांत्रिक संवाद की कमी की ओर संकेत करता था। आलोचकों का मानना रहा कि अरविंद केजरीवाल ने धीरे-धीरे पार्टी को एक 'हाई-कमांड' मॉडल की ओर मोड़ दिया, जहां अंतिम निर्णय एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गया। यह वही मॉडल था, जिसकी आलोचना 'आप' अपने शुरुआती दौर में करती थी।

दिल्ली विधानसभा में लगातार दो कार्यकाल तक सरकार चलाना 'आप' की बड़ी उपलब्धि रही। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली-पानी जैसे क्षेत्रों में किए गए प्रयोगों को व्यापक सराहना

मिली। 'मोहल्ला क्लिनिक' और सरकारी स्कूलों के सुधार जैसे मॉडल को अन्य राज्यों ने भी अपनाने की कोशिश की। लेकिन, शासन की सफलता संगठनात्मक एकता की गारंटी नहीं बन सकी। पार्टी के भीतर असंतोष पनपता गया। कई वरिष्ठ नेताओं ने या तो दूरी बना ली या पूरी तरह अलग हो गए। इससे यह धारणा मजबूत हुई कि पार्टी का विस्तार तो हुआ, लेकिन उसकी आंतरिक लोकतांत्रिक संरचना कमजोर पड़ती गई।

हाल के घटनाक्रम जिनमें कथित रूप से सांसदों का एक साथ पार्टी छोड़ना और राघव चड्ढा की भूमिका 'आप' के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि, राजनीतिक संदर्भों का विश्लेषण आवश्यक है। लेकिन, यह परिदृश्य पार्टी के लिए गंभीर संकट का संकेत है। दलबदल कानून के तहत दो-तिहाई सदस्यों के साथ पार्टी छोड़ने से सदस्यता बचाने की रणनीति यह दिखाती है कि राजनीतिक गणित अब 'आप' में भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जितना अन्य दलों में।

अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक और स्पष्ट राजनीतिक शैली रही है। उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया, जो सीधे जनता से संवाद करता है और प्रशासनिक निर्णय लेने में तेज है। लेकिन, यही शैली उनकी कमजोरी भी बन सकती है। अत्यधिक केंद्रीकरण, असहमति को सीमित करना और नेतृत्व का व्यक्तिवादी स्वरूप ये सभी कारक किसी भी संगठन को लंबे समय में कमजोर कर सकते हैं। 'आप' का उदाहरण इस संदर्भ में अध्ययन का विषय बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 'आप' का भविष्य क्या होगा? क्या यह पार्टी अपने शुरुआती आदर्शों की ओर लौट पाएगी या फिर यह भी एक पारंपरिक राजनीतिक दल बनकर रह जाएगी? एक ओर, पार्टी के पास अभी भी एक मजबूत वोट बैंक, शासन का अनुभव और एक पहचाना हुआ नेतृत्व है। दूसरी ओर, संगठनात्मक टूटन, नेतृत्व पर निर्भरता और वैचारिक स्पष्टता की कमी जैसी चुनौतियां सामने हैं। यदि अरविंद केजरीवाल पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक संवाद को पुनर्जीवित करते हैं। नए नेतृत्व को उभरने का अवसर देते हैं और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करते हैं, तो 'आप' फिर से अपनी खोई हुई विश्वसनीयता हासिल कर सकती है। लेकिन, अगर वर्तमान प्रवृत्तियां जारी रहती हैं, तो यह पार्टी धीरे-धीरे अपनी विशिष्ट पहचान खो सकती है और भारतीय राजनीति में एक और 'सामान्य' दल बनकर रह जाएगी।

'आम आदमी पार्टी' की कहानी केवल एक राजनीतिक दल की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस उम्मीद की कहानी है जो भारतीय जनता ने एक वैकल्पिक राजनीति से जोड़ी थी। अरविंद केजरीवाल के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे उस उम्मीद को फिर से जीवित कर सकें। राजनीति में करिश्मा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन, स्थायित्व के लिए संस्थागत मजबूती और सामूहिक नेतृत्व अनिवार्य है। 'आप' का भविष्य इसी संतुलन पर निर्भर करेगा और यही इस पार्टी की असली परीक्षा भी है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार, 25 अप्रैल 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए राज्यसभा में फिर नोटिस

- इस पर 73 सांसदों के दस्तखत, मार्च में दोनों सदनों में खारिज हो चुका प्रस्ताव

नई दिल्ली (एजेंसी)। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष ने शुक्रवार को राज्यसभा में नोटिस दिया। इस पर 73 सांसदों के दस्तखत हैं। इससे पहले मार्च में विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में नोटिस दिया था। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इन नोटिसों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोप उन्हें हटाने के लिए आवश्यक उच्च संवैधानिक मानदंडों को पूरा नहीं करते। लोकसभा में सीईसी को हटाने के प्रस्ताव के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। राज्यसभा में इसके लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश जरूरी होती है।

देशभर में मेडिकल स्टूडेंट्स की छुट्टी रद्द

नीट एग्जाम के लिए सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। मई में होने जा रहे नीट यूजी 2026 से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नेशनल मेडिकल कमिशन ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजों को जरूर निर्देश दिया है। एनएमसी ने सभी मेडिकल कॉलेजों से कहा है कि वे नीट एग्जाम से पहले किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को 2 और 3 मई 2026 को छुट्टी नहीं देंगे। यानी अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट इन दो दिनों में छुट्टी प्लान कर रहा है या पहले से छुट्टी अप्रूव है तो उनकी छुट्टी रद्द कर दी जाएगी। एनटीए ने सभी मेडिकल कॉलेजों से नीट एग्जाम से पहले मेडिकल स्टूडेंट्स को छुट्टी न देने के लिए कहा है। आयोग ने कॉलेजों के नाम एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में सभी मेडिकल कॉलेजों को यह सलाह दी जाए कि वे 2 मई और 3 मई 2026 को छात्रों को छुट्टी न दें।

बिहार में सम्राट सरकार को हासिल हो गया बहुमत

- अब कैबिनेट विस्तार की टकटकी बंगाल चुनाव का है इंतजार

पटना (एजेंसी)। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया। विधानसभा में ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। विश्वास मत पर बहस के बाद सदन में सत्ता पक्ष के पक्ष में बहुमत रहा, जबकि विपक्ष संख्या बल के मामले में काफी पीछे रह गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने प्रस्ताव के पास होने की घोषणा कर दी। इसके साथ कैबिनेट मंत्री बनने के ख्वाहिशमंदों को 29 अप्रैल का इंतजार है, जब बंगाल चुनाव का आखिरी दिन होगा। बिहार विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से पहले से ही वोटिंग की संभावना कम थी। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए 122 वोटों की आवश्यकता थी।

पहले झालमुड़ी अब नाव की सवारी, मोदी का बंगाल में 'खेला'

प्रधानमंत्री ने नाव चलाने वाले को गले लगाया, 1000 रुपए भी दिए

कोलकाता (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हुगली नदी में नाव की सवारी की है। इस दौरान पीएम ने खुद से फोटोग्राफी भी की। तस्वीरों में वे हाथ में कैमरा लिए नजर आ रहे हैं। उन्होंने नाविकों से बातचीत भी की। हुगली में नाव की सवारी कराने वाले नाविक को एक हजार रुपए भी दिए।

पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाव की सवारी वाली तस्वीरें शेयर की। उन्होंने लिखा, 'हर बंगाली के लिए गंगा का एक बहुत ही खास स्थान है। यह कहना गलत नहीं होगा कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है।' इससे पहले पीएम 19 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान झाड़ग्राम में रास्ते में वह एक दुकान पर रुके और झालमुड़ी खाई। पीएम मोदी ने कोलकाता के हुगली घाट पर नाव की सवारी के बाद नाविक गौरांगो बिस्वास को गले लगाया और 1000 रुपए दिए। पीएम ने × पर एक वीडियो शेयर कर लिखा- कल शाम हावड़ा से कोलकाता तक लंबे रोड शो के दौरान हावड़ा ब्रिज पर था। आज सुबह उसे हुगली नदी से देखा।

19 अप्रैल को पीएम ने बंगाल में झालमुड़ी खाई

पीएम मोदी रविवार 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने झाड़ग्राम में एक दुकान पर रुके और झालमुड़ी खाई। झालमुड़ी बनाते हुए दुकानदार ने पूछा, 'आप प्याज खाते हैं। पीएम ने जवाब दिया- हां प्याज खाता हूं बस दिमाग नहीं। यह सुनकर दुकानदार हंसने लगा।' पीएम ने दुकानदार से इस मुलाकात का करीब 40 सेकेंड का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। साथ ही कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं।

गैस लीकेज से धमाका, रिटायर्ड इंजीनियर की मौत

ब्यावरा (नप्र)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में गैस लीकेज से जोरदार धमाका हुआ। हादसे में ब्यावरा की शिवधाम कॉलोनी निवासी 85 वर्षीय रिटायर्ड इंजीनियर सुरेश सिंह भल्ला की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी पद्मावती भल्ला गंभीर रूप से झुलस गईं। अस्पताल में इलाज जारी है।

जानकारी के मुताबिक, घटना सुबह करीब 6 बजे हुई, जब रसोई में चूल्हा जलाने की कोशिश की जा रही थी। घर में लगे गैस सिलेंडर से रातभर धीमी गति से गैस रिसती रही। बंद कमरे में गैस भरती गई, लेकिन परिवार को इसकी भनक नहीं लगी।

बंगाल में मतदाता सूची से 65 चुनाव अधिकारियों के नाम कटे, एससी पहुंचा मामला

चुनाव कराएंगे, मगर खुद अपना वोट नहीं दे पाएंगे

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात 65 अधिकारियों के नाम ही मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इससे नाराज इन अधिकारियों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल, चुनाव आयोग के आदेश पर बंगाल में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया था। इस कवायद में पूरे राज्य से 90.8 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। हैरानी की बात यह है कि चुनाव संपन्न कराने वाले 65 अधिकारियों के नाम भी इस सूची से गायब हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील एमआर शमशाद ने कोर्ट में कहा, ये 65 अधिकारी चुनाव ड्यूटी पर हैं। इनके ड्यूटी आर्डर पर वोटर आईडी नंबर भी दर्ज है, लेकिन अब वो नंबर ही डिलीट कर दिए गए हैं। जो लोग चुनाव करवा रहे हैं, वही वोट नहीं डाल पाएंगे। यह मनमाना फैसला है। कई लोगों को नाम हटाने की वजह तक नहीं बताई गई। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, अपनी दलीलें अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने रखें। जस्टिस जयमाल्य बागची ने टिप्पणी की, ट्रिब्यूनल उचित आदेश देगा। इस चुनाव में शायद ये वोट न दे पाएं, लेकिन मतदाता सूची में बने रहने का इनका ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

सीजेआई बोले- बंगाल का वोटर टर्नआउट देखकर बहुत खुश हूं

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुई रिकॉर्ड वोटिंग की तारीफ की। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपिन पंचोली की बेंच ने राज्य में चुनावी हिंसा न होने पर संतोष जताया। सीजेआई ने कहा- भारत के नागरिक के रूप में, मुझे मतदान प्रतिशत देखकर बहुत खुशी हुई। जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, कि वे लोग समाधान के लिए कोर्ट की तरफ से नियुक्त 19 अपीलीय ट्रिब्यूनलों से संपर्क करें। कोर्ट बंगाल की याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था।

हम एक ही जहाज के मुसाफिर डूबेंगे तो साथ डूबेंगे: एनएसए

- मुस्लिम समुदाय के चुनिंदा लोगों के साथ बैठक में बोले एनएसए अजीत डोभाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और भारतीय मुस्लिम समुदाय के चुनिंदा लोगों के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में बीते 18 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में मुस्लिम समुदाय से आने वाले अलग-अलग क्षेत्रों के लोग शामिल थे। इस बैठक के दौरान एनएसए ने कहा कि भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमान एक ही जहाज के मुसाफिर की तरह हैं। आपको बता दें कि इस बैठक का उद्देश्य पारंपरिक वोट-बैंक की राजनीति से परे हटकर मुस्लिम समुदाय के विकास, शिक्षा और उद्यमिता के भविष्य पर चर्चा करना था। डोभाल ने कहा, हम (हिंदू और मुसलमान) एक ही जहाज पर सवार हैं। हम या तो साथ तैरेंगे या साथ डूबेंगे! इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रसिद्ध शिक्षाविद् ने किया।

फैक्ट्री में तिलक-बिंदी प्रतिबंध का विरोध

हिंदू उत्सव समिति ने किया प्रदर्शन, कर्मचारियों को बांधा कलावा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के एमपी नगर स्थित एक निजी कंपनी में कर्मचारियों के धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध को लेकर विवाद गहरा गया है। हिंदू उत्सव समिति ने इस फैसले का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।

समिति के अध्यक्ष चन्द्रशेखर तिवारी ने आरोप लगाया कि कंपनी ने नोटिस जारी कर कर्मचारियों को तिलक, अंगूठी, कड़ा, बाली, मंगलसूत्र और बिंदी जैसे धार्मिक प्रतीक पहनकर आने से मना किया है। उन्होंने इसे धार्मिक आस्था और परंपराओं पर आघात बताते हुए कहा कि इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कर्मचारी का दावा- तिलक लगाने पर निकाला बाहर- एक कर्मचारी ने दावा किया कि जब वह कलावा और तिलक लगाकर फैक्ट्री पहुंचा, तो उसे बाहर कर दिया गया। इससे कर्मचारियों में नाराजगी का माहौल है।

कंपनी का पक्ष—प्रोडक्ट क्वालिटी का हवाला- फैक्ट्री के मैनेजर वीएस राजपूत ने बताया कि यह सर्कुलर कंपनी की ओर से जारी किया गया था। उनका कहना है कि इन वस्तुओं के उपयोग से प्रोडक्ट रिजेक्ट होने की संभावना रहती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि समिति की मांग पर विचार किया जाएगा और नोटिस वापस लेने की कोशिश की जाएगी।

एएपी को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा

- टोटल 10 में से 7 सांसदों ने छोड़ दिया केजरीवाल का साथ

नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भाजपा जॉइन कर ली है। शुक्रवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे। चड्ढा ने कहा कि उनके साथ पार्टी के दो-तिहाई सांसद भी भाजपा में शामिल होंगे। अशोक मित्तल के घर 15 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी। उन्होंने कहा कि क्रिकेटर हरभजन सिंह और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी उनके साथ हैं। दोनों एएपी के राज्यसभा सांसद हैं। चड्ढा ने कहा- पिछले कुछ सालों से, मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं। हमने यह फैसला किया है कि हम संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को बीजेपी में मिला लेंगे। उन्होंने कहा-जिस एएपी को मैंने अपने खून-पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वह अब अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिकता से भटक गई है। अब यह पार्टी देश के हित में नहीं, बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करती है। राघव चड्ढा ने कहा- राज्यसभा में आप के 10 सांसद हैं, जिनमें से दो-तिहाई, यानी 7 हमारे साथ हैं। इनके नाम-राघव चड्ढा,संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता,विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल।

सात महीने की प्रेग्नेंट नाबालिग को अबॉर्शन की इजाजत

एससी ने कहा- उसे डिलीवरी के लिए मजबूर नहीं कर सकते

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सात महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट 15 साल की लड़की को मेडिकल टर्मिनेशन (अबॉर्शन) की इजाजत दी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा- यह जन्म लेने वाले बच्चे का सवाल नहीं है। जरूरी यह है कि लड़की क्या चाहती है। अगर वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता।

- सुप्रीम कोर्ट बोला- यह महिला की खुद की इच्छा का सवाल है

भले ही बच्चे को जन्म के बाद गोद देने का ऑप्शन मौजूद हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इस स्टेज पर अबॉर्शन करना मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने डिलीवरी के बाद बच्चा गोद देने का सुझाव दिया था। कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। लड़की एक नाबालिग लड़के के साथ आपसी सहमति से संबंध के बाद प्रेग्नेंट हुई थी। नाबालिग की मां ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में तय समयसीमा से आगे जाकर बेटी के अबॉर्शन की इजाजत मांगी थी। लड़की ने भी कहा था कि वह प्रेग्नेंसी जारी नहीं रखना चाहती।

कोर्ट बोला- महिला को प्रजनन संबंधी फैसले लेने की आजादी

कोर्ट ने कहा, 'किसी महिला, खासकर नाबालिग, को इच्छा के खिलाफ प्रेग्नेंसी पूरा करने के लिए मजबूर करना उसके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। इसलिए उसकी इच्छा का सम्मान करना जरूरी है।' कोर्ट ने कहा कि प्रजनन संबंधी फैसले लेने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का हिस्सा है। इसलिए गोद देने का विकल्प किसी महिला को जबरन बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर अदालतें अनचाही गर्भावस्था को जारी रखने पर जोर देंगी, तो महिलाएं अवैध अबॉर्शन सेंटर्स का सहारा लेने या छिपकर गर्भपात कराने को मजबूर हो सकती हैं। इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बढ़ जाएगा।

अमेरिका ने तैयार किया ईरान की 'घेराबंदी' का प्लान

युद्धविराम खत्म होते ही होर्मुज में भयानक बमबारी, सीक्रेट है मिशन

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी सेना के अधिकारी नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं ताकि अगर ईरान के साथ मौजूदा संघर्ष-विराम टूट जाता है तो होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की क्षमताओं को निशाना बनाया जा सके। सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कई तरह के प्लान पर विचार किए जा रहे हैं। जिनमें एक विकल्प ये है कि होर्मुज स्ट्रेट, दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के आसपास ईरान की क्षमताओं पर टारगेटेड हमले किए जाएंगे। सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इन संभावित हमलों में छोटी, तेज गति वाली हमलावर नौकाओं, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाजों और अन्य ऐसे असममित संसाधनों को निशाना बनाया जा सकता है जिनकी मदद से तेहरान ने इन महत्वपूर्ण जलमार्गों को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया है और अमेरिका के खिलाफ सौदेबाजी के हथियार के तौर पर उनका इस्तेमाल किया है।

ईरान की सैन्य क्षमता नष्ट करने में नाकाम अमेरिका- सैन्य योजना से परिचित एक सूत्र के हवाले से सीएनएन ने कहा है जब तक आप पूरी तरह से यह साबित नहीं कर देते कि ईरान की 100 फीसदी सैन्य क्षमता नष्ट हो चुकी है या लगभग यह पक्का न हो जाए कि अमेरिका अपनी क्षमताओं से इस जोखिम को कम कर सकता है तब तक यह इस बात पर निर्भर करेगा कि (ट्रंप) इस जोखिम को उठाने और जलडमरूमध्य से जहाजों को गुजारना शुरू करने के लिए किस हद तक तैयार हैं।

होर्मुज में हमले का नया प्लान बना रहा अमेरिका!

इस नाकेबंदी की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी उथल-पुथल मच गई है जिससे अमेरिकी मुद्रास्फीति को कम करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। अमेरिका में इस साल होने वाले मध्यावधि चुनावों पर इसका असर दिखने की संभावना है। हालांकि अमेरिकी सेना ने ईरान की नौसेना को निशाना बनाया है लेकिन शुरुआती एक महीने के युद्ध में अंदरूनी ईरान में ज्यादातर हमले किए गये।

पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का बड़ा दावा

चीन गतिरोध में सरकार ने कभी अकेला नहीं छोड़ा

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व आर्मी चीफ चीफ जनरल एमएम नरवणे ने गुरुवार को कहा कि 2020 में चीन के साथ गतिरोध में सरकार ने सेना को अकेला नहीं छोड़ा था। सरकार पूरी तरह से सपोर्ट में थी और पूरा अधिकार दिया था कि हालात बिगड़ने पर चीनी सैनिकों पर गोलियां चला सकें। जनरल नरवणे ने गुरुवार को कुछ चैनल्स को दिए इंटरव्यू में अपनी किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' से जुड़े विवादों पर बात की। इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, 'जो उचित समझो वह करो' टिप्पणी सशस्त्र बलों पर सरकार के पूरे भरोसे को दर्शाती है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जमीनी स्थिति का जवाब देने के लिए सशस्त्र बलों को फ्री हैंड दिया गया था।

अगर सरकार को कुछ सही नहीं लगा तो ठीक है

जब उनकी पुरानी किताब को अभी तक रक्षा मंत्रालय से क्लियरेंस न मिलने को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मेरी किताब में कुछ बहुत संवेदनशील था, लेकिन अगर सरकार को लगा कि कुछ बातें सही नहीं बैठ रही हैं, तो ठीक है।' आगे भारत-चीन सीमा विवाद पर उन्होंने कहा कि रेचिन ला में सेनाएं आमने-सामने थीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने स्थिति को और बिगड़ने नहीं दिया और अपने लक्ष्यों को हासिल किया।

मॉरिशस हिन्दी स्पीकिंग यूनियन को संबोधित करेंगे विनय उपाध्याय

भोपाल। हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय मॉरिशस की हिन्दी स्पीकिंग यूनियन ने जाने-माने कला समीक्षक तथा उद्घोषक विनय उपाध्याय को 'मास्टर ऑफ सेरेमनी' स्किल प्रशिक्षण कार्यशाला में बतौर विशेष वक्ता आमंत्रित किया है। 25 मई को सुबह 9 बजे मंच संचालन कला-कौशल पर केन्द्रित इस अनूठे कार्यक्रम का शुभारंभ मॉरिशस स्थित महात्मा गांधी संस्थान में होगा। वर्चुअल लिंक के ज़रिए विनय प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। यह गतिविधि कला और संस्कृति मंत्रालय मॉरिशस सरकार के सहयोग से आयोजित की जा रही है।

इस अवसर पर हिन्दी स्पीकिंग यूनियन

मॉरिशस की चेअर परसन डॉ. अंजलि चिंतामुनि तथा महात्मा गांधी संस्थान की हिन्दी प्राध्यापक डॉ. तनुजा पुदारूथ भी उपस्थित रहेंगी। इस कार्यशाला में सैकड़ों प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2024 में साहित्य और कलाओं का अंतरराष्ट्रीय महोत्सव मॉरिशस स्थित विश्व हिन्दी सचिवालय में वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ था। विनय उपाध्याय इस महोत्सव के मुख्य उद्घोषक तथा सांस्कृतिक समन्वयक थे। उनके मंच संचालन कौशल को वहाँ की गणमान्य विभूतियों तथा दर्शक-श्रोताओं ने बेहद सराहा था। दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के समारोहों के संचालन हेतु विनय उपाध्याय आमंत्रित किये जाते रहे हैं। वे अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत कला समीक्षक, लेखक तथा सम्पादक हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रख्यात रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर किया नमन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय चेतना के प्रखर स्वर और ओजस्वी काव्यधारा के अमर रचनाकार रामधारी सिंह 'दिनकर' की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 'रश्मिरथी' और 'परशुराम की प्रतीक्षा' जैसी कृतियों के सृजन से दिनकर जी ने स्वाभिमान, संघर्ष और राष्ट्र धर्म का संदेश दिया। उनकी लेखनी से देशवासियों को सत्य और साहस के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा मिलती है।

रंग, रेखा और विचार का संगम- 'मूविंग फार्म्स' वर्ककैंप 11 मई से भोपाल में

भोपाल। पिछले वर्ष की अपार सफलता के बाद, आर्ट डिज़ाइन टीचर्स फ़ोरम एक बार फिर कला शिक्षा को नई दृष्टि देने के उद्देश्य से 'मूविंग फ़ॉर्म्स – वर्ककैंप नामक पाँच दिवसीय रचनात्मक आवासीय कार्यशाला का आयोजन 11 से 15 मई 2026 के बीच अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, भोपाल परिसर में कर रहा है।

यह वर्ककैंप अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, भोपाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मध्यप्रदेश के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

इस कार्यशाला का उद्देश्य कला शिक्षकों को एक ऐसा साझा मंच प्रदान करना है, जहाँ वे कला, शिल्प और डिज़ाइन के माध्यम से रचनात्मक शिक्षण की नई संभावनाओं को समझ सकें। पाँच दिवसीय इस आवासीय कार्यक्रम में प्रतिभागियों को अनुभवी कलाकारों, डिज़ाइनरों, शिल्पियों और शिक्षाविदों के साथ संवाद और कार्य करने का अवसर मिलेगा। क्यूरेटर सुनिल शुक्ल ने बताया कि प्रस्तावित आवासीय वर्ककैंप में प्रसिद्ध चित्रकारों, अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय और एनआईडी भोपाल के संकाय सदस्यों, ओडिशा एवं राजस्थान के शिल्पियों तथा एनसीईआरटी, नई दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा सत्र संचालित किए जाएंगे, जो अपने आप में विशिष्ट और अनूठे होंगे।यह वर्क कैंप मुख्यत: मध्यप्रदेश के कला एवं डिज़ाइन शिक्षकों के लिए है, हालांकि सीमित संख्या में अन्य राज्यों के शिक्षक, शिक्षण में रूचि रखने वाले नव कला स्नातक (एम.एफ़.ए., बी.डेस./ एम.डेस.) तथा बच्चों के साथ कार्य करने वाले पेशेवर कलाकार भी आवेदन कर सकते हैंद्य इच्छुक प्रतिभागी गूगल फार्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नि:शुल्क है और अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। अधिक जानकारी के लिए 8989649700 पर संपर्क करें।

पानी की आपूर्ति और साफ-सफाई व्यवस्था में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे : ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

ऊर्जा मंत्री शहर की सीवर, सफाई व्यवस्था देखने सुबह 6 बजे विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचे

भोपाल (नप्र)। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शुक्रवार सुबह 6 बजे उप नगर ग्वालियर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर पेयजल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था, सीवर व्यवस्था का औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री ने सुबह 6 बजे वाटर सीवरेज पंपिंग स्टेशन पीएचई कॉलोनी में पहुंचकर नगर निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ सीवरेज सफाई व्यवस्था देखी और जरूरी निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने वार्ड 4 के चद्र नगर, ठाकुर मोहल्ला, वार्ड 1 के रामाजी का पुरा, आरआर टॉवर पहुंचकर सीवर व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सड़क और विद्युत व्यवस्था तथा

वार्ड 36 के गेंडे वाली सड़क और शिंदे की छावनी में पहले किये गये निरीक्षण के दौरान दिए निर्देश पर हुई कार्यवाही को देखा। उन्होंने निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर निगम अधिकारियों को तुरंत सफाई व्यवस्था में सुधार करने हेतु निर्देशित किया।

सुपर सकर मशीन से सफाई कार्य का निरीक्षण – ऊर्जा मंत्री श्री तोमर की पहल पर जनकल्याण समिति द्वारा नगर निगम के सहयोग से उप नगर ग्वालियर में सीवर लाइनों की सफाई के लिए चलाए जा रहे अभियान के निरंतर 7वें दिवस शुक्रवार को हजीरा चौराहे पर पहुंचकर सुपर सकर मशीन से चल रही सीवर लाइनों की सफाई के काम का भी निरीक्षण किया। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि अब आधुनिक तकनीक के माध्यम से सफाई व्यवस्था और अधिक तेज, प्रभावी व सुदृढ़ बनेगी। उन्होंने कहा कि हमने सीवर सफाई के कार्य को अपने हाथ में लिया है और हम इसमें बदलाव लाकर दिखाएंगे। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि स्वच्छता, सुविधा और बेहतर जीवन स्तर बनाना हमारा संकल्प है।

उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा एवं लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने शुक्रवार को मंदसौर में जिला चिकित्सालय में 100 बेड के नव निर्मित वार्ड का लोकार्पण किया।

करुणाधाम में भव्य शिवार्चना केन्द्र का हुआ भूमि-पूजन, शिवालय का शिखर होगा 150 फीट ऊँचा

भोपाल। करुणाधाम आाश्रम में पीठाधीश्वर गुरुदेव श्री सुदेश शाण्डिल्य महाराज के निर्देशन में भव्य शिवालय शिवार्चना केन्द्र का भूमि-पूजन पूजन-अर्चन एवं विधि-विधान से किया गया। भव्य शिवालय का शिखर 150 फीट ऊँचा होगा। गुरुदेव श्री शांडिल्य महाराज ने बताया कि लगभग 55 हजार वर्गफुट क्षेत्र में बनने वाला शिवालय प्रमुख धार्मिक केन्द्र आस्था, वास्तुकला और साज-सज्जा सहित आधुनिक सुविधाओं के अद्भुत संगम का केन्द्र बनने जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 22 करोड़ होगी, जिसे पूरा करने में करीब 4 वर्ष लगेंगे। शिवालय का निर्माण राजस्थान के प्रसिद्ध धौलपुर पत्थर से किया जायेगा। इसकी मजबूती और भारतीय स्थापत्य शैली प्राचीनता को दर्शायेगी। शिवालय परिसर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, एक समग्र आध्यात्मिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा। परिसर में हरियाली, फाउण्टेन और पार्क का निर्माण भी होगा, जिससे श्रद्धालुओं को शांत और सकारात्मक वातावरण की अनुभूति होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये बेसमेंट पार्किंग की व्यवस्था भीड़ नियंत्रण में सहायक होगी। इसके अलावा परिसर में पुस्तकालय का निर्माण होगा, जिसमें धार्मिक ग्रंथों के साथ अन्य ज्ञानवर्द्धक पुस्तकों का संग्रहण किया जायेगा। मेडिटेशन के लिये विशेष ध्यान कक्ष भी बनाया जा रहा है। यह पूरी परिकल्पना धार्मिक आस्था को सशक्त बनाने के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास का नया आयाम भी स्थापित करेगी।

आप के पूर्व विधायक कैंडिडेट ने पिता के सिर में गोली मारी

वारदात के बाद बोला- 'अभी और कत्ल होंगे' घरों में दुबके परिजन और पड़ोसी

बड़वानी (नप्र)। आम आदमी पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ चुके एक व्यक्ति ने अपने पिता के माथे पर गोली मार थी। परिवार में जमीन और रुपयों के विवाद में उसने अपने पिता की जान ले ली। आरोपी फरार है, लेकिन सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर अपनी मां-भाई और अन्य सदस्यों को धमकी दे रहा है। वह साल 2018 में बड़वानी से विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। जिले के पिछोड़ी गांव में पिता की हत्या करने वाला आरोपी चंदन बडोले राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहा है और वर्ष 2018 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर बड़वानी विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। हालांकि, उसे उस चुनाव में करीब एक हजार वोट ही मिले थे। वारदात के 48 घंटे बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के

अनुसार, बड़वानी जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर पिछोड़ी गांव में 32 वर्षीय चंदन बडोले ने बीते 4 दिन पहले अपने 58 वर्षीय पिता जगन बडोले की कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था, जो पहले भी पैसों की मांग को लेकर मारपीट कर चुका था और जमीन बेचने का दबाव बना रहा था। उन्होंने आशंका जताई कि आरोपी परिवार के अन्य सदस्यों को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

छोटे भाई को भी चंदन से जान का खतरा – छोटे भाई कुंदन ने भी डर व्यक्त करते हुए कहा कि चंदन कभी भी घर आकर हमला कर सकता है। फिलहाल पुलिस बल घर के बाहर तैनात है।

सोशल मीडिया पर सक्रिय, धमकी भी दे रहा – पुलिस के अनुसार, आरोपी जंगलों में छिपा हुआ है और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर धमकियां दे रहा है। घटना से तीन दिन पहले उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर अपने पिता से संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग का जिक्र किया था। वीडियो में उसने बड़े व्यापार और राजनीति में आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा भी जताई थी।

मां ने सुनाई आरोपी बेटे की क्रूरता की कहानी – घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिससे पूरे गांव में भय का वातावरण है। ग्रामीणों का कहना है कि रात में लोग घरों के बाहर सोने से भी डर रहे हैं। मृतक की पत्नी गौरी बाई ने बताया कि आरोपी घटना के दिन हिंसक रूप ले बैठा।

बीए पास, दो दफा हेड कांस्टेबल के लिए चयन

चंदन बडोले ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव पिछोड़ी से प्राप्त की और बड़वानी पीजी कॉलेज से बीए किया था। वह दो बार मध्य प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल पद के लिए चयनित हुआ, लेकिन दोनों बार शारीरिक परीक्षा में असफल रहा। इसके बाद वह अवैध रेत खनन और परिवहन के कार्य में लिप्त हो गया।

बलजीत सिंह बिसेन, कोतवाली थाना प्रभारी ने कहा कि पिता की कनपटी पर गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी बेटा चंदन जंगल में छिपा है, वह सोशल मीडिया पर सक्रिय है। कई थानों की पुलिस उसकी घेराबंदी कर रहीं हैं, जल्द गिरफ्तार होगा।

सतना में कुपोषण से चार माह की बच्ची की मौत

● प्रशासन ने झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक को किया सील

सतना (नप्र)। मझगवां विकासखंड में कुपोषण के चलते एक बार फिर मातम पसर गया है। सुरांगी निवासी नत्थू प्रजापति की 4 महीने की बेटी सुप्रांशी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि उसका जुड़वां भाई नैतिक गंभीर हालत में रीवा के पीआईसीयू में भर्ती है। दोनों बच्चे जन्म के बाद से ही गंभीर कुपोषण का शिकार थे, लेकिन सिस्टम की अनदेखी और अंधविश्वास के चलते समय पर इलाज नहीं मिल सका।

शासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिला – मृत बच्ची की मां विमला ने रोते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मां का कहना है कि टीकाकरण के अलावा उन्हें शासन की किसी भी अन्य योजना का लाभ नहीं मिला। आशा कार्यकर्ता ने कभी घर आकर संपर्क नहीं किया और न ही कोई सलाह दी। जांच में सामने आया कि मां बच्चों को स्तनपान कराने में असमर्थ थी, जिसके कारण उन्हें गाय और बकरी का दूध दिया जा रहा था। विशेषज्ञों के अनुसार, 6 माह तक केवल मां का दूध ही अनिवार्य है, लेकिन परिवार को सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था।

झोलाछाप के जाल में फंसा रहा परिवार

बच्चा पिछले 15 दिनों से उल्टी, दस्त और बुखार से तड़प रहा था, लेकिन परिजन उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय जुगुलपुर गांव के झोलाछाप डॉक्टर प्रेमलाल अनुरागी के पास ले जाते रहे। झोलाछाप ने लालच में आकर बच्चों की गंभीर स्थिति को छिपाया और खुद ही इलाज करता रहा। जब हालत हद से ज्यादा बिगड़ गई, तब मंगलवार को उन्हें मझगवां सीएससी ले जाया गया, जहां से उसे सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया।

झोलाछाप का क्लिनिक सील, केस दर्ज – मामले की गंभीरता को देखते हुए सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बुधवार रात मझगवां एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर और बीएमओ की संयुक्त टीम ने झोलाछाप प्रेमलाल के दवाखाने पर छापा मारा। क्लिनिक से 100 तरह की अवैध दवाइयां जब्त कर उसे सील कर दिया गया है। आरोपी प्रेमलाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और म.प्र. रूजोपचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी, सतना ने कहा जन्म के समय बच्चों का वजन सामान्य (करीब 2.9 किलो) था, लेकिन 4 माह बाद यह वजन बढ़ने के बजाय खतरनाक स्तर तक गिर गया, जो स्पष्ट रूप से मॉनिटरिंग की कमी को दर्शाता है।

सुपरवाइजर और कार्यकर्ता को नोटिस – महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी राजीव सिंह ने इस बड़ी चूक के लिए सेक्टर सुपरवाइजर करुणा पांडेय और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूजा पांडेय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद विधायक प्रीतम लोधी के बदले तेवर, मांगी माफी

भोपाल(नप्र)। बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने गुरुवार को एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने के मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद बढ़ गया था। लोधी ने कहा कि जब पुलिस ने उनके बेटे को सार्वजनिक रूप से घुमाया, तो उन्हें गहरा दुख हुआ और भावनाओं में आकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके लिए वे दिल से माफी मांगते हैं। उनका यह बयान भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात के बाद आया। लोधी ने कहा कि आगे से वे अपने शब्दों का ध्यान रखेंगे और पार्टी के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को अपना जवाब सौंप दिया है और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।

एक दिन पहले जारी किया था नोटिस – एक दिन पहले हेमंत खंडेलवाल ने पिछोर के विधायक प्रीतम सिंह लोधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में उनके व्यवहार को बेहद आपत्तिजनक और पार्टी अनुशासन के खिलाफ बताया गया था और तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया था।

वीडियो सामने आने के बाद बढ़ा विवाद– यह विवाद उस समय शुरू हुआ, जब लोधी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे करैरा के एसडीओपी आयुष जाखड़ से बहस करते नजर आए और उनके अधिकार पर सवाल उठाते दिखे। वीडियो में उन्होंने कहा कि करेरा उनके बाप की जागीर नहीं है और उनका बेटा वहां आएगा और चुनाव लड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो उसे रोककर दिखाए।

मार्च निकालने की दी चेतावनी

उन्होंने बड़ी संख्या में समर्थकों को इकट्ठा कर अधिकारी के घर तक मार्च निकालने की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद उनके बयान की व्यापक आलोचना हुई।

थार कांड से जुड़ा है मामला

यह मामला 16 अप्रैल को हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें लोधी के बेटे दिनेश लोधी पर आरोप है कि उन्होंने थार एसयूवी से पांच लोगों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में दो महिलाएं और तीन पुरुष घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर वाहन को जब्त कर लिया था, जिसके बाद विधायक और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया।

आईपीएस एसोसिएशन ने भी की थी कार्रवाई की मांग

इस मुद्दे पर व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली। भारतीय पुलिस सेवा एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की और इसे प्रशासनिक व्यवस्था का अपमान बताया। वहीं, विपक्ष ने भी भाजपा पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पार्टी पर गलत कामों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

राजस्थान की गर्म हवा ने मप्र में बढ़ाई तपिश

भोपाल, जबलपुर-उज्जैन समेत 11 जिलों में लू का अलर्ट; नर्मदापुरम् में स्कूलों की छुट्टी

भोपाल (नप्र)। राजस्थान से आ रही गर्म हवा से मध्य प्रदेश में तपिश बढ़ गई है। भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, नर्मदापुरम और सागर संभाग के शहरों में हीट वेव यानी लू जैसे हाल हैं। शुक्रवार को भी 11 जिलों में लू का अलर्ट है। नर्मदापुरम में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार, शुक्रवार को जिन शहरों में लू चलने का अलर्ट है, उनमें निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, रतलाम, झाबुआ, धार और अलीराजपुर शामिल हैं।

इससे पहले गुरुवार को प्रदेश में पारा सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा। नर्मदापुरम में तापमान सबसे ज्यादा 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। छतरपुर जिले के खजुराहो में 43.4 डिग्री और नौगांव में 43 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। सीधी में 42.6 डिग्री, दतिया, दमोह, सागर-टीकमगढ़ में 42.2 डिग्री, रायसेन-रतलाम में 42 डिग्री, सतना में 41.8 डिग्री, मंडला में 41.6 डिग्री, गुना-रीवा में 41.5 डिग्री, नरसिंहपुर-खरगोन में 41.4 डिग्री, श्योपुर में 41.2 डिग्री, शाजापुर, खंडवा-दतिया में 41.1 डिग्री, उमरिया में 41 डिग्री तापमान रहा। प्रदेश के 5 बड़े शहरों की बात करें तो जबलपुर में 41.6 डिग्री, भोपाल में 41 डिग्री, ग्वालियर में 40.8 डिग्री, इंदौर में 40.6 डिग्री और उज्जैन में 40 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच गया।

नर्मदापुरम् रात में भी गर्म – भोपाल समेत कई शहरों में रात में तापमान 25 से 27 डिग्री के आसपास ही चल रहा है। नर्मदापुरम में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक है। यहां आने वाले दिनों में वॉर्म नाइट की स्थिति भी बन सकती है। वॉर्म नाइट मौसम की एक ऐसी स्थिति है, जब रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ज्यादा होता है।

संपादकीय

'आप' को तगड़ा झटका

'आम' आदमी पार्टी के दल के वरिष्ठ नेता और पिछले दिनों राज्यसभा में दल के नेता पद से हटाए गए राघव चड्ढा ने तगड़ा झटका दिया है। पार्टी के 10 में से 7 राज्य सभा सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी में विलय का ऐलान कर दिया है। खुद राघव चड्ढा और उनके सात साथियों ने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी है। हालांकि आप नेता इसके पीछे केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 'साजिश' बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे असली कारण पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मनमानी कार्यशैली है। पार्टी के यह झटका इसलिए भी बहुत बड़ा इसलिए है, क्योंकि अगले साल पंजाब में जहां, आप सत्तारूढ़ है, विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आप की इस फूट का असर निचले स्तर तक दिखेगा। राघव चड्ढा के साथ रास सांसद संदीप पाठक और अशोक मित्तल के पत्रकार वार्ता में कहा कि हमने तय किया है कि हम, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के दो तिहाई सदस्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा स्वाति मालीवाल और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी भाजपा में शामिल होंगे।

दरअसल पार्टी के भीतर इस नई अंतर्कलह की शुरूआत आम आदमी पार्टी द्वारा इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर की ज़िम्मेदारी राघव चड्ढा की जगह अशोक कुमार मित्तल को देने से शुरू हुई थी। तब राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के फ़ैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वह जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं और सवाल पूछा कि इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ होगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचा और जिसे मैंने अपनी युवावस्था के 15 साल दिए, वह अब अपने सिद्धांतों, मूल्यों और बुनियादी नैतिकताओं से पूरी तरह भटक चुकी है। अब यह पार्टी देश या राष्ट्रीय हित के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि निजी स्वार्थ के लिए काम कर रही है। राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब देश या राष्ट्रीय हित के लिए काम नहीं कर रही है। बल्कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य कर रही है। मजे की बात है कि राघव चड्ढा के साथ अशोक मित्तल भी भाजपा में जा रहे हैं।चूंकि आप के दो तिहाई रास सांसद भाजपा में शामिल होंगे, इसलिए उन पर दलबदल कानून लागू नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं और तीन सांसद लोकसभा में शामिल हैं। लोस के तीनों सांसद पंजाब से जीते हैं। असल में केजरीवाल और राघव चड्ढा में दूरियां उसी दिन से नजर आने लगी थीं, जब केजरीवाल जेल में थे और राघव अपनी पत्नी परिणीति के साथ लंदन में मौज मस्ती की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। राघव को लोकसभा चुनाव में भी पंजाब से दूर रखा गया। औपचारिक तौर पर वे श्री आनंदपुर साहब सीट पर नजर आए थे। एक जमाने में राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के काफी नजदीकी माने जाते थे। 2015 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे 2019 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2020 में राजेंद्र नगर से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें आम आदमी पार्टी का पंजाब प्रभारी बनाया गया। 2022 को आप ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया। वे दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से 2022 तक विधायक रह चुके हैं। आप में जो कुछ हो रहा है, वो पार्टी के गर्त में जाने की निशानी है। केजरीवाल की मनमानी से अधिकांश नेता परेशान हैं और दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं।

समुद्री व्यापार, बीमा संकट और भारत की चुनौतियाँ

नजरिया

अंशुमान

लेखक संसद टीवी से जुड़े पत्रकार हैं।

अमेरिका, इजरायल और ईरान के टकराव ने एक अहम बात सामने रखी कि अगर जहाज़ों को पर्याप्त बीमा कवर नहीं मिलता, तो बैंक और वित्तीय संस्थाएं पैसा देने से पीछे हट जाती हैं, और कंपनियां माल भेजने से मना कर देती हैं। यानी सिर्फ बीमा महंगा होने से ही व्यापार रुक सकता है, भले ही समुद्र में कोई सीधी लड़ाई न हो रही हो। अगर हम सारी परिस्थितियों को भारत जैसे देश के नजरिये से देखेंगे तो यह समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति खासतौर पर चिंताजनक है, क्योंकि उसका ज्यादातर व्यापार समुद्र के रास्ते होता है।

ईरान द्वारा होरमुज़ जलडमरूमध्य बंद करने का असर बहुत ज्यादा पड़ा। इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों की संख्या अचानक बहुत कम हो गई और पहले के मुकाबले 10 प्रतिशत से भी नीचे आ गई। यह कमी सिर्फ हमलों की वजह से नहीं हुई, बल्कि एक बड़ी वजह यह भी थी कि बीमा बहुत महंगा हो गया और मिलना भी मुश्किल हो गया। मार्च 2026 तक, बड़े अंतरराष्ट्रीय बीमा समूहों ने खाड़ी क्षेत्र में युद्ध से जुड़े जोखिम का बीमा देना कम कर दिया या बंद करने की चेतावनी दे दी। इसका सीधा असर यह हुआ कि जहाज़ों का बीमा बहुत महंगा हो गया। पहले जहां बीमा का खर्च 0.15-0.25 प्रतिशत था, वहीं बढ़कर 5-10 प्रतिशत प्रति यात्रा हो गया।

अगर इस स्थिति को थोड़ा विस्तार से समझें, तो पता चलता है कि हर एक समुद्री यात्रा पर लगभग 10 से 14 मिलियन डॉलर तक का अतिरिक्त खर्च जुड़ गया। यह खर्च इतना ज्यादा था कि तेल या अन्य सामान ले जाना कंपनियों के लिए लाभदायक नहीं रह गया। यानी जहाज़ चलाना तो संभव था, लेकिन आर्थिक रूप से यह समझदारी भरा फैसला नहीं था। इसी वजह से, बिना किसी आधिकारिक या सैन्य रोक के भी यह समुद्री रास्ता लगभग बंद जैसा हो गया। कंपनियों ने खुद ही जोखिम और बढ़ती लागत के कारण पीछे हटने लगीं। ऊपर से अमेरिका के कुछ प्रतिबंधों ने हालात को और जटिल बना दिया, जिससे समुद्री व्यापार और प्रभावित हुआ। यह पूरी घटना हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाती है कि आज के दौर में व्यापार सिर्फ युद्ध या सैन्य टकराव से ही नहीं रुकता। बीमा की बढ़ती कीमतें, वित्तीय अनिश्चितता और जोखिम का डर भी उतना ही बड़ा असर डालते हैं। कई बार ये आर्थिक कारण ही ऐसे हालात पैदा कर देते हैं, जहां रास्ता खुला होने के बावजूद व्यापार ठप हो जाता है।

अमेरिका, इजरायल और ईरान के टकराव ने एक अहम बात सामने रखी कि अगर जहाज़ों को पर्याप्त बीमा कवर नहीं मिलता, तो बैंक और वित्तीय संस्थाएं पैसा देने से पीछे हट जाती हैं, और कंपनियां माल भेजने से मना कर देती हैं। यानी सिर्फ बीमा महंगा होने से ही व्यापार रुक सकता है, भले ही समुद्र में कोई सीधी लड़ाई न हो रही हो। अगर हम सारी परिस्थितियों को भारत जैसे देश के नजरिये से देखेंगे तो यह समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति खासतौर पर चिंताजनक है, क्योंकि उसका ज्यादातर व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। आंकड़ों के अनुसार, भारत का 95 प्रतिशत से ज्यादा व्यापार मात्रा के हिसाब से और करीब 70 प्रतिशत मूल्य के हिसाब से समुद्री मार्गों से होता है। इसलिए अगर समुद्री रास्तों में कोई भी रुकावट आती है, तो उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय नाविकों यानी सीफेयरर्स पर भी पड़ता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े समुद्री श्रमिकों में से एक है। जब बीमा कवर कम होता है या जहाज़ों की आवाजाही रुकती है, तो ये नाविक कई तरह की समस्याओं में फंस जाते हैं जैसे कई बार जहाज़ पर ही फंसे रहना, वेतन में देरी, और घर वापस लौटने में दिक्कत।

लगातार यह सब परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने इसके समाधान के लिए 1.38 अरब डॉलर यानी कि करीब 12,980 करोड़ रुपये का भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बनाया है। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल का उद्देश्य जहाज़, माल, और युद्ध-जोखिम जैसे मामलों में घरेलू स्तर पर बीमा सुविधा देना है, खासकर उन रास्तों के लिए जो ज्यादा जोखिम भरे हैं। यह एक अच्छा कदम है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अभी और मजबूत व्यवस्था की जरूरत है।सबसे महत्वपूर्ण समुद्री बीमा को समझना भी काफी जरूरी है, क्योंकि यह अलग-अलग हिस्सों में काम करता है और हर हिस्सा अलग तरह के जोखिम को कवर करता है। सबसे पहले हुल एंड मशीनरी बीमा होता है, जो जहाज़ को होने वाले भौतिक नुकसान को कवर करता है जैसे दुर्घटना, टक्कर या तकनीकी खराबी। दूसरा P&I यानी प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी बीमा होता है, जो तीसरे पक्ष से जुड़े नुकसान को कवर करता है। इसमें समुद्र में प्रदूषण फैलना, माल का खराब होना या खो जाना, और चालक दल को चोट लगना जैसी स्थितियां शामिल होती हैं। इसके अलावा, युद्ध या संघर्ष जैसी असामान्य परिस्थितियों के लिए अलग से और महत्वपूर्ण वार रिस्क बीमा लिया जाता है, क्योंकि ऐसे जोखिम सामान्य बीमा में शामिल नहीं होते और इनके लिए अतिरिक्त कवर की जरूरत पड़ती है।

इनमें से युद्ध जोखिम बीमा सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। इसकी कीमत लंदन की एक समिति तय करती है, जो किसी भी क्षेत्र को उच्च जोखिम घोषित कर सकती है। ऐसा होते ही 72 घंटे के अंदर बीमा महंगा हो सकता है या बंद भी हो सकता है। खास बात यह है कि बीमा कंपनियां खतरा बढ़ने का इंतजार नहीं करतीं, बल्कि पहले ही प्रीमियम बढ़ा देती हैं। और एक बार बढ़ जाने के बाद ये जल्दी कम भी नहीं होते, भले ही हालात सुधर जाएं।वर्तमान में समय के साथ समुद्री बीमा एक पूरी तरह बाजार आधारित व्यवस्था बन गया है। सरकारें इसे एक रणनीतिक साधन की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ एक खर्च के रूप में देखती रही हैं। लेकिन होरमुज़ संकट ने दिखाया कि बीमा व्यवस्था ही यह तय कर सकती है कि व्यापार चलता रहेगा या रुक जाएगा खासकर विकासशील देशों के लिए। भारत की स्थिति इस मामले में थोड़ी कमजोर है। क्योंकि दुनिया के कुल जहाज़ों में भारत की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से भी कम है, इसलिए वह अंतरराष्ट्रीय बाजार या बीमा नियमों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता। इस वजह से भारत को बाहरी बीमा कंपनियों और बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है।हाल के समय में भारत ने कुछ सुधार जरूर किए हैं। जैसे, देश ने अपने तेल भंडार बढ़ाए हैं, रेलीफ जैसी योजनाएं शुरू की हैं और सरकारी बीमा कंपनी जीआईसी रे की क्षमता भी बढ़ाई है। 2022 में जीआईसी रे ने कुछ जोखिम वाले देशों के लिए बीमा कवर देने की पहल भी की थी। लेकिन समस्या यह है कि ये कदम ज्यादातर तब उठाए जाते हैं जब संकट आ चुका होता है। पहले से तैयारी करने के बजाय, बाद में प्रतिक्रिया दी जाती है।

नीति स्तर पर भी कुछ कदम उठाए गए हैं। आईआरडीएआई देश के बीमा क्षेत्र की देखरेख करता है, जबकि जीआईएफटी सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में आईएफएससीए विदेशी बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों को भारत में काम करने के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत चाहता है कि बड़ी अंतरराष्ट्रीय बीमा कंपनियां यहां आकर अपना कारोबार शुरू करें, ताकि देश में ही बेहतर बीमा सुविधाएं मिल सकें और विदेशी बाजारों पर निर्भरता कम हो। जीआईएफटी सिटी को एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां ऐसी कंपनियों को आसान नियम और बेहतर माहौल दिया जाता है, ताकि वे भारत में निवेश करें और बीमा सेवाएं उपलब्ध कराएं।

लेकिन अभी भी भारत के प्रयास बिखरे हुए और पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। देश के पास ऐसा मजबूत तंत्र नहीं है जो संकट के समय बीमा लागत को नियंत्रित कर सके या लगातार बीमा कवर उपलब्ध करा सके। इसके अलावा, भारतीय बीमा कंपनियां भी अपने जोखिम का बड़ा हिस्सा विदेशी कंपनियों को सौंप देती हैं, जिससे बाहरी निर्भरता बनी रहती है। भारत के लिए एक और चिंता की बात यह है कि उसका लगभग 30 प्रतिशत कच्चा तेल और 54 प्रतिशत एलपीजी इसी होरमुज़ रास्ते से आता है। जब बीमा महंगा होता है, तो माल ढुलाई की लागत भी बढ़ती है, जिससे देश में महंगाई बढ़ने का खतरा होता है। भारत के पास तेल भंडार तो हैं, लेकिन वे सिर्फ भौतिक कमी के लिए हैं, बढ़ती लागत से निपटने के लिए नहीं।इस संकट का असर भारतीय नाविकों पर भी साफ दिखा। लगभग 80 प्रतिशत भारतीय नाविक विदेशी जहाज़ों पर काम करते हैं और विदेशी बीमा पर निर्भर हैं। जब बीमा कम होता है, तो ये नाविक फंस सकते हैं या उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता। इस संकट में करीब 23,000 भारतीय नाविक प्रभावित हुए और सैकड़ों लोग जहाज़ों पर ही फंसे रह गए। एक बड़ी समस्या यह भी है कि भारत में अलग-अलग मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी है। वित्त मंत्रालय, जहाज़रानी मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच कोई एक ऐसा संस्थान नहीं है जो तुरंत फैसले ले सके। संकट के समय त्वरित कार्रवाई जरूरी होती है, लेकिन अभी ऐसा तंत्र पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है।

समुद्री जोखिमों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सबसे पहले एक मजबूत और केंद्रीय संस्था की जरूरत है, जो सभी संबंधित विभागों और मंत्रालयों को एक साथ जोड़ सके और संकट के समय तेज़ी से निर्णय ले सके। अभी अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण समय पर कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक एकीकृत व्यवस्था बहुत जरूरी है। इसके साथ ही, सरकार को एक बड़ा और सशक्त जोखिम फंड बनाना चाहिए, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सक्रिय हो सके और जहाज़ों के लिए बीमा कवर को बनाए रखे। इससे व्यापार अचानक रुकने से बचेगा और कंपनियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

भारत को अपनी विदेशी बीमा पर निर्भरता कम करने के लिए जल्द से जल्द अपना खुद का पी एंड आई क्लब यानी प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी क्लब शुरू करना चाहिए। इससे जहाज़ों और व्यापार से जुड़े बीमा के लिए देश को विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। संकट के समय भारत के पास खुद का नियंत्रण रहेगा और बीमा व्यवस्था ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद बनी रहेगी। इसके साथ ही, देश के अंदर बीमा और पुनर्बीमा की क्षमता को भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि भारत अपने ही स्तर पर ज्यादा जोखिम संभाल सके, ताकि बड़े और मुश्किल मामलों में भी बाहर की कंपनियों पर कम निर्भर रहना पड़े। इससे पूरी व्यवस्था ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बन सकेगी।वैश्विक हालातों और टकरावों को देखकर यह समझना जरूरी है कि समुद्री बीमा सिर्फ एक खर्च नहीं, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा का अहम हिस्सा है। होरमुज़ संकट ने यह दिखा दिया कि व्यापार सिर्फ युद्ध से नहीं, बल्कि बीमा और वित्तीय व्यवस्था से भी रुक सकता है। इसलिए भारत को आगे के लिए ऐसी मजबूत और पहले से तैयार व्यवस्था बनानी होगी, जो किसी भी संकट में व्यापार को जारी रख सके और देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखे।

भारतीय सड़कें, एलन मस्क की मशीन और विधिक चक्रव्यूह

सड़क का ज्ञान

डॉ. सुधीर कुमार

(कुरुक्षेत्र विवि में सहायक प्रोफेसर)

जब एलन मस्क की टेस्ला और उसकी 'फुल सेल्फ-ड्राइविंग' तकनीक की बात होती है, तो यह किसी भविष्यवादी हॉलीवुड फिल्म जैसा रोमांच पैदा करती है। लेकिन कल्पना कीजिए, वही कार जब बनारस की संकरी गलियों या दिल्ली के उन व्यस्त चौराहों पर उतरती है जहाँ नियमों की किताब नहीं बल्कि 'सड़क का अंतर्ज्ञान' चलता है, तो तकनीक के पसीने छूट जाते हैं। भारत में टेस्ला की संभावित असफलता का डर विशुद्ध तकनीक से कहीं अधिक 'सांस्कृतिक और विधिक' है। यहाँ की सड़कें केवल एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का मार्ग नहीं हैं, बल्कि वे एक जीवंत, गतिशील और पूरी तरह से अप्रत्याशित 'इकोसिस्टम' हैं।

पश्चिमी दुनिया में सड़कों को एक 'मैथमेटिकल ग्रिड' की तरह देखा जाता है, जबकि भारत में सड़क एक 'लिविंग केओस' (जीवंत अराजकता) है, जहाँ एक ई-रिक्शा का अचानक मुड़ना या सड़क के बीच स्थित किसी मज़ार या मंदिर का होना कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक ऐसा 'लॉजिकल एरर' है, जिसका समाधान कैलिफोर्निया की कोडिंग लाइनों में मौजूद ही नहीं है। टेस्ला के स्वायत्त इंजन के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसका 'स्टेरिल डेटा' और 'ऑप्टिकल रिकॉग्निशन' की संकीर्ण सीमाएं हैं। मस्क का कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन अनुशासित सड़कों पर प्रशिक्षित है जहाँ 'लेन' की पवित्रता अनिवार्य है और हर वाहन का एक मानक आकार होता है। इसके उलट, भारतीय सड़कों पर 'मिश्रित ट्रैफिक' का ऐसा राज है जिसे कोई एल्गोरिथ्म आज तक डिकोड नहीं कर पाया। यहाँ एक ही सड़क पर बैलगाड़ी, साइकिल और हाई-स्पीड एस.यू.वी. के साथ ऐसे ऑटो और ई-रिक्शा चलते हैं जो कभी रंग-बिरंगे तिरपाल से ढके होते हैं तो कभी उन पर बेतरतीब लोहे के पाइप लदे होते हैं।

टेस्ला का सेंसर इन 'नॉन-स्टैंडर्ड' आकृतियों को 'वाहन' के रूप में वर्गीकृत करने के बजाय एक 'अज्ञात वस्तु' मानकर 'फ्रीज' हो जाता है। इसके अलावा, यहाँ 'इशारों की मूक भाषा' चलती है - जहाँ एक ड्राइवर हाथ बाहर निकालकर मोड़ काटने का संकेत देता है। इस 'सड़क के मिजाज' और बिना इंडिकेटर मुड़ने वाले ऑटो चालक के दिमाग को पढ़ने के लिए टेस्ला को 'केओस मॉडलिंग' की जरूरत है, वरना सिलिकॉन वैली की यह मशीन भारत की जीवंत सड़कों पर केवल हाँफती नजर आएगी। कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो टेस्ला का भारत में प्रवेश एक अभूतपूर्व 'विधिक चक्रव्यूह' खड़ा करता है, जिसका केंद्र 'उत्तरदायित्व' का प्रश्न है। भारतीय कानून, विशेषकर रैयलैंड्स बनाम फ्लेचर (1868) से निकले 'कठोर दायित्व' और एमसी मेहता (1987) के 'पूर्ण दायित्व' के सिद्धांतों पर टिका है। यदि कोई स्वायत्त कार किसी ई-रिक्शा या आवारा पशु को पहचान नहीं पाती और दुर्घटना होती है, तो कंपनी यह तर्क देकर नहीं बच सकती कि यह 'सॉफ्टवेयर ग्लिच' था। कानून की नजर में एक खतरनाक मशीन को सार्वजनिक सड़क पर लाना ही निर्माता को पूर्णतः जिम्मेदार बना देता है।

इसके साथ ही, भारतीय न्याय संहिता के तहत 'मेंस रिया' यानी 'आपराधिक इरादे' की अवधारणा है। एक सॉफ्टवेयर को न तो जेल भेजा जा सकता है और न ही कैलिफोर्निया में बैठे कोडर को अंतरराष्ट्रीय कानूनी पेचों के बीच आसानी से 'लापरवाही' के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह एक ऐसा कानूनी शून्य है जहाँ अपराधी (कोड) तो है, लेकिन दंड पाने के लिए कोई 'भौतिक देह' नहीं। नैतिक धरातल पर, प्रसिद्ध 'ट्रॉली प्रॉब्लम' भारत में एक गंभीर 'संवैधानिक चुनौती' बन जाती है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त 'जीवन का अधिकार' यहाँ सर्वोच्च है। यदि टेस्ला का कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसी धार्मिक ढांचे (मज़ार या मंदिर) को बचाने के लिए कार को मोड़ता है और उससे किसी राहगीर की जान जाती है, तो यह सीधे तौर पर जीवन के अधिकार का हनन है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996) जैसे ऐतिहासिक फैसलों ने जीवन की जिस पवित्रता को स्थापित किया है, उसे कोई विदेशी एल्गोरिथम अपनी गणनाओं से चुनौती नहीं दे सकता।

साथ ही, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 'डिजाइन डिफेक्ट' का जोखिम मस्क की कंपनी के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि भारत की विशिष्ट बाधाओं (सड़क के बीच के पेड़, पशु, धार्मिक स्थल) के लिए सेंसर को कस्टमाइज़ न करना एक 'गंभीर सेवा दोष' माना जाएगा। साक्ष्यों के स्तर पर भी, अर्जुन पंडितराव खोतकर (2020) का फैसला इलेक्ट्रॉनिक डेटा के लिए सख्त प्रमाणन की मांग करता है; यदि टेस्ला का डेटा विदेशी सर्वर में है, तो भारतीय पुलिस के लिए 'डेटा संप्रभुता' के बिना न्याय सुनिश्चित करना नामुमकिन होगा। अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे विकसित देशों में सड़कें केवल आने-जाने का रास्ता नहीं हैं, बल्कि वे एक अनुशासित गलियारे की तरह काम करती हैं। वहाँ का पूरा सिस्टम इतना व्यवस्थित है कि वह टेस्ला जैसी सेल्फ-ड्राइविंग कारों के लिए एक सटीक प्रयोगशाला बन जाता है। इन देशों में सड़कों की चौड़ाई, साइनबोर्ड की ऊँचाई और ट्रैफिक लाइट की जगह पहले से पूरी तरह तय और फिक्स होती है।

कंप्यूटर के लिए ऐसे माहौल को समझना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ अचानक सड़क पर किसी जानवर के आने, कोई धार्मिक ढांचा सामने पड़ने या बेतरतीब भीड़ जमा होने का खतरा नहीं होता। चीन ने तो 'स्मार्ट रोड' तकनीक को अपना लिया है, जहाँ सड़क पर लगे सेंसर खुद कार को जानकारी दे देते हैं कि आगे क्या रुकावट है। इसे 'सहयोगात्मक समझ' कहा जाता है। पश्चिमी देशों में कानूनी स्थिति भी बहुत साफ है। मर्सिडीज जैसी बड़ी कंपनियों ने यह जिम्मेदारी ली है कि अगर कार 'ऑटो-पायलट' मोड पर है और कोई दुर्घटना होती है, तो उसका दोषी ड्राइवर नहीं बल्कि खुद कंपनी होगी। वहाँ डेटा की सुरक्षा और इंश्योरेंस (बीमा) से जुड़े नियम भी पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी हैं। इसके विपरीत, पश्चिमी देशों में सड़क एक 'निर्वात' की तरह होती है जहां सिर्फ गाड़ियां चलती हैं, लेकिन भारत में सड़क एक 'मल्टी-परपज पब्लिक स्क्वायर' (बहुउद्देशीय सार्वजनिक स्थल) की तरह है। यहाँ सड़कों पर शादियाँ होती हैं, राजनीतिक रैलियां निकलती है और यहाँ तक कि डिवाइडर के बीच भी जीवन (लोग या जानवर) बसता है।

एलन मस्क का 'प्रिडिक्टिव एनालिसिस' (अनुमान लगाने वाली तकनीक) भारत में आकर 'पैरालिसिस' (ठप) हो जाता है। इसका कारण यह है कि भारतीय सड़कों पर 'तर्क' या लॉजिक से ज्यादा इंसान के 'प्रतिक्षेप' यानी तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता काम करती है। भारत में 'एल्गोरिथमिक पक्षपात' भी एक बहुत बड़ा खतरा है। उदाहरण के लिए, यदि कार को किसी महंगी लग्जरी गाड़ी और एक गरीब के सब्जी के ठेले के बीच किसी एक को टक्कर मारने का चुनाव करना पड़े, तो क्या उसका निर्णय संपत्ति के मूल्य (सस्ती या महंगी चीज) पर आधारित होगा? ऐसे सवाल सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के दायरे में आ जाते हैं। भारत जैसे देश में एक 'सॉफ्टवेयर एरर' (तकनीकी गलती) को केवल एक खामी नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे एक 'सामाजिक अन्याय' के रूप में देखा जाएगा।

जब तक मस्क के इंजीनियर बनारस की गलियों में 'अराजकता का संगीत' नहीं सुनेंगे और जब तक भारत सरकार एक 'नियामक परीक्षण ढांचे' के जरिए देयता नियमों को स्पष्ट नहीं करती, तब तक ये कारें केवल एक महंगा खिलौना बनी रहेंगी। भारत को केवल 'स्मार्ट कार' नहीं, बल्कि 'सांस्कृतिक रूप से सजग कृत्रिम बुद्धिमत्ता' चाहिए। मस्क की असली 'अग्निपरीक्षा' इसी बात में है कि क्या वे अपनी 'यूनिवर्सल कोडिंग' के अहंकार को त्याग कर भारतीय सड़कों के 'ऑर्गेनाइज्ड केओस' के सामने नतमस्तक होंगे? क्योंकि भारत में कार केवल एक मशीन नहीं है, और यहाँ का कानून किसी भी मशीन की तुलना में 'मानवीय संवेदना' और 'सामाजिक व्यवस्था' को सदैव वरीयता देगा।

रिकॉर्ड मतदान के क्या संकेत हैं?

बंगाल विधानसभा चुनाव

विवेक कुमार साव

लेखिक एच.के.बी.के. डिग्री कॉलेज, कर्नाटक में सहायक आचार्य हैं।

पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 152 विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान को देखकर आम जनता से लेकर राजनीतिक विश्लेषक तक हैरान हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस चरण में मतदान प्रतिशत 92.35 प्रतिशत तक पहुँच गया, जबकि 2021 के इन्हीं क्षेत्रों में यह 82.03 प्रतिशत रहा था। कुल मतदाताओं की संख्या में भले ही कोई कहे कि भारी वृद्धि न दिख रही हो (वोट कटने जे कारण), लेकिन प्रतिशत में यह उछाल महज संयोग नहीं है। यह बंगाल की राजनीति के मौजूदा ध्रुवीकरण, सामाजिक-आर्थिक कारकों और रणनीतिक गणनाओं का परिणाम है। सबसे पहले, यह चुनाव पूरी तरह द्विध्रुवीय (बाइपोलर) हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी लड़ाई में वामपंथी और कांग्रेस जैसे तीसरे मोर्चे के लिए जगह बहुत कम बच गई है। 2021 में इन 152 सीटों में बीजेपी ने 59 सीटें जीती थीं (कुल 77 में से), जबकि टीएमसी का दबदबा कायम रहा। इस बार भी जमीनी स्तर के विश्लेषक यही मान रहे हैं कि बीजेपी को 59 से 70 सीटों तक पहुँचने का मौका तो मिल सकता है, लेकिन 100 सीटों का लक्ष्य नामुमकिन सा लगता है। कुछ विशेषज्ञ तो बीजेपी के 5-10 सीटों के नुकसान की भी संभावना जता रहे हैं, जबकि टीएमसी सौ सीटों के करीब भी पहुँच सकती है। कांग्रेस को मुश्किल से 2-3 सीटें और वामपंथियों को एक के आसपास ही नजर आ रहा है, हालाँकि उनके वोट प्रतिशत में मामूली बढ़ोतरी संभव है।

बंगाल के बाहर काम करने वाले लाखों बंगाली श्रमिकों (खासकर बेंगलुरु, गुजरात और अन्य राज्यों से) में यह धारणा घर कर गई थी कि एसआईआर और नागरिकता संबंधी विवादों के चलते अगर वे घर आकर वोट नहीं डालेंगे तो उनकी नागरिकता पर सवाल उठ सकता है। स्टेशनों पर भीड़ इसका जीता-जागता प्रमाण थी। इस डर ने अप्रवासी वोटर को मजबूती से बंगाल लौटने को मजबूर किया। एक नजर इसपर भी डालें कि मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा। मुस्लिम मतदाता लगभग पूरी तरह टीएमसी के पक्ष में कंसोलिडेट दिखें। कांग्रेस, वामपंथी या छोटी पार्टियाँ (जैसे हुमायूँ कबीर की) इस बार भी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पल्ले में करने में नाकाम रहीं। यह बंगाल में मुस्लिम राजनीति के भविष्य के लिए भी एक बड़ा संदेश है। चुनाव में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर वोट डाला। ममता बनर्जी की लोकप्रिय 'लक्ष्मी भंडार' योजना का असर यहाँ स्पष्ट दिखा। हालांकि सोशल मीडिया पर आए कुछ वीडियो यह भी संकेत देते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण ने एक खास वर्ग की महिलाओं को भी प्रभावित किया है। दूसरी तरफ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि केंद्र की सुरक्षा बलों की मजबूत उपस्थिति ने उन मतदाताओं का भय दूर किया जिन्हें पहले हिंसा या दबाव के डर से घर बैठना पड़ता था। इससे कुल मतदान में इजाफा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिसीमन विधेयक को लेकर बनाया गया माहौल उतना प्रभावी साबित नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद की थी। वहीं, एसआईआर के खिलाफ गुस्सा और धार्मिक ध्रुवीकरण दोनों ही ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। कौन-सी ताकत ज्यादा प्रभावी साबित होगी, यह 4 मई को परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा। अब सवाल यह कि किसे फायदा, किसे नुकसान? यदि बीजेपी को कोई विशेष लाभ दिखना है तो यही पहला चरण होगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह भी है कि टीएमसी को पहले चरण में कोई बहुत भारी नुकसान का कोई ठोस संकेत अभी नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर यह रिकॉर्ड मतदान बंगाल की राजनीति में एक 'सुनामी' की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन यह सुनामी किसकी होगी, यह अभी अनिश्चित है। क्या यह बीजेपी के नेतृत्व में परिवर्तन का संकेत है, या फिर ममता बनर्जी के समर्थन में जनता का एक और सैलाब? दोनों पक्ष अब दूसरे चरण (29 अप्रैल) की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन पहले चरण का यह आंकड़ा पहले ही बता चुका है, बंगाल की लड़ाई अब और भी तीखी, और भी द्विध्रुवीय हो चुकी है। बंगाल की आम जनता इस समय एक अजीब-सी मौनता में डूबी हुई नजर आ रही है। कोई खुलकर अपनी राय व्यक्त करने को तैयार नहीं है। एक ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सामाजिक विमर्श और बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाकर जनता को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेता राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए खुलकर धार्मिक ध्रुवीकरण की रणनीति अपना रहे हैं। यह स्पष्ट है कि जनता का यह मौन 29 अप्रैल को मतदान के माध्यम से मुखर हो जाएगा। आखिर में एक सवाल अनुत्तरित रह जाता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर इतनी जल्दबाजी में लाखों मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाना अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। एक बात अब निर्विवाद रूप से साफ हो चुकी है कि भाजपा इस चुनाव को 'मोदी बनाम ममता' और 'हिन्दू बनाम मुस्लिम' के द्वंद्व में बदलना चाहती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे पूरी तरह 'बंगाली अस्मिता' और 'बंगाल की गरिमा' का मुद्दा बनाने पर जोर दे रही है। इससे दोनों पार्टियों को फायदा मिलेगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ.महेन्द्र अग्रवाल

लेखक व्यंग्यकार हैं।

हर जगह खुदा है!

खुदा है ,पर मेरा आशय यहां उनसे नहीं है। हर जगह खुदा है का मेरा मतलब अपने शहर और शहर की सड़कों से है। जहां देखो वहां खुदा पड़ा है। हालत यह है कि आप न चौपहिया वाहन से चल सकते हैं ,न दोपहिया वाहन से और न पैदल फिर आम आदमी क्या करे? किसी को घर से दफ्तर जाना है,किसी को विद्यालय-महाविद्यालय जाना है,किसी को सब्जी लानी है तो किसी को किराना। घर से बाहर निकले बिना कोई भी काम नहीं होता और आदमी फालतू निठल्ला भी हो तो घर में कब तक बैठे ? पास पड़ोस की खबर भी लेगा ,पार्क सिनेमा भी जाएगा ,यार दोस्तों से भी गपियाएगा । लेकिन घर से बाहर निकलकर सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है।

सरकार को विकास के नाम पर वोट मिलते हैं इसलिए केन्द्र की हो या प्रदेश की सबका विकास पर बड़ा जोर है। विकास के लिए रोज़ नई योजनाएं आ रही हैं।करोड़ों का बजट आ रहा है।जनता की सुविधाओं के लिए जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है क्योंकि पूरा जोर विकास पर है। शहर में आने वाली किसी भी योजना की बात सुनकर जनता भी खुश हो जाती है और बजट का नाम सुनते ही सरकारी कर्मचारी की बांछें खिल उठती हैं। जैसे मिलन के समय किसी प्रेमी के दिल की कली कली खिल उठती है, उसी तरह ।बजट आबंटित होते ही जन प्रतिनिधि भी निश्चिंत हो जाते हैं।कारण अब सबको पता हैं कोई छुपाने की बात तो है नहीं।इसलिए सभी एडवांस में अपनी आवश्यक गतिविधियां शुरू कर देते हैं।जल परियोजना आई तो शहर से बीस किलोमीटर दूर की नदी से पानी की लाइन बिछाने के लिए शहर की एक-एक सड़क एक-एक गली खोदकर पटक दी गई। फिर उसे इसी मलबे से आधा अधूरा ऊपर नीचे उल्टा सीधा पाट दिया ।फिर सीबर योजना का नाटक शुरू हुआ तो फिर दोबारा शहर की खुदाई शुरू हो गई ।बिना किसी तैयारी के जगह-जगह सड़क खोद कर खाली लाइन डाल दी गई कि बाद में जोड़ेंगे । अब बाद में जुड़ना है तो सड़कें कैसे बनें।बाद में पता चलाकि ठेकेदार-इंजीनियर के गठजोड़ ने फाइल में बनाकर पेमेंट निकलवा लिया ।फिर अगले महीने घर-घर कनेक्शन देने का खेल शुरू हुआ तो फिर खुदवा दीं कि कोई शिकायत भी करे तो मामला पकड़ में न आये।सबसे कनेक्शन के पैसे जमा करवा कर लाइन घर के आगे निकाल कर छोड़ दी कि अब प्रतीक्षा करो ।नया बजट आये तो लाइनें जुड़वा दें।फिर पानी आएगा या फिर सीबर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू होगा तो फिर नए कनेक्शन होंगे तब एक बार फिर सड़क का बिल बन जायेगा।तब तक खाली पाइपों से हवा की आवाज सुनो या उफनते सीबर चैंबरों से फैलती बदबू का आनंद लो।

सहन करते करते डेढ़ साल हो गया तो लोग चीखने चिल्लाने लगे। तो फिर नए कनेक्शन के नाम पर सड़क के दोनों किनारे खोद कर पटक दिए ताकि आम आदमी को पैदल भी न चलना पड़े। घर के बाहर ही न निकले,चौबीस घंटे आराम। इधर दस साल में बार-बार प्रोजेक्ट राशि बढ़ने से फिर-फिर फाइलें चलती हैं ,बार-बार नया बजट आता है । फिर फिर इसे इधर-उधर ठिकाने लगाकर योजना को लटका कर फिर से मांग शुरू हो जाती है।जो जहां खुदा है उसकी किसी को परवाह नहीं है। उनका कहना है की सरकारी योजनाएं गोपनीय क्यों रहे? और विकास कार्य लगातार चल रहे हैं यह पब्लिक को खुद अपनी आंखों से देखना भी चाहिए। सरकारें झूठ थोड़ी बोलती हैं।

दृष्टिकोण

-मानवी श्रीवास्तव

समानता से हासिल होगा सशक्तिकरण

यह असमानता बचपन से ही महिलाओं के आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। दूसरा बड़ा कारण आर्थिक निर्भरता है। जब तक कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होता, तब तक वह अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकता। यही स्थिति महिलाओं के साथ भी रही है। लंबे समय तक महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित रखा गया, जबकि आर्थिक निर्णय पुरुषों के हाथों में रहे। आज भी अनेक महिलाएँ परिवार की आय में योगदान देने के बावजूद आर्थिक निर्णयों में भाग नहीं ले पातीं। इसलिए महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है।शिक्षा महिलाओं के अधिकारों का सबसे मजबूत आधार है। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करती है। एक शिक्षित महिला न केवल स्वयं सशक्त होती है, बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी सशक्त बनाती है।

मानव के विकास और विस्तार के क्रम को आगे बढ़ाने में स्त्री-पुरुष की एक समान भागीदारी है। पुरुषों की भांति स्त्रियों ने भी सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास में उतना ही सहयोग है जितना पुरुषों ने, महिलाएँ केवल जीवन की उत्पत्ति का माध्यम ही नहीं हैं, बल्कि वे परिवार, समाज और संस्कृति की आधारशिला भी होती हैं। उनके बिना समाज की कल्पना अधूरी है। इसके बावजूद, आज के आधुनिक युग में भी महिलाओं से जुड़े अनेक मुद्दे जैसे असमानता, शिक्षा की कमी, सुरक्षा और अधिकार अब भी चिंतनीय और विचारणीय बने हुए हैं।इसी संदर्भ में नारी वंदना अधिनियम जैसे राजनीतिक मुद्दे ने एक बार फिर महिलाओं के अधिकार, अवसर और विकास के प्रश्न को सामने ला खड़ा किया है। यद्यपि यह अधिनियम अभी पूरी तरह ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाया है, फिर भी यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या केवल एक अधिनियम ही महिलाओं को वास्तविक समानता दिला सकता है? किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तभी मानी जाती है, जब वहाँ महिलाओं को पुरुषों के समान सम्मान, अवसर और अधिकार प्राप्त हों। महिलाएँ केवल परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली सदस्य नहीं हैं, बल्कि वे समाज और राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण शक्ति हैं। इसके बावजूद लंबे समय तक महिलाओं को समाज में पुरुषों की तुलना में कम अवसर दिए गए। शिक्षा, रोजगार, संपत्ति, राजनीति और निर्णय लेने के अधिकार जैसे अनेक क्षेत्रों में महिलाओं को पीछे रखा गया। समय के साथ परिस्थितियाँ बदली हैं, लेकिन अभी भी पूर्ण समानता का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। हाल के वर्षों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ी है। विशेष रूप से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर कई महत्वपूर्ण चर्चाएँ हुई हैं। वर्ष 2023 में महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया। इस विधेयक ने महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में आशा जगाई। यह केवल राजनीतिक अधिकारों की बात नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में बराबरी का स्थान मिलना चाहिए। महिलाओं को समान अधिकार न मिलने के पीछे कई सामाजिक और मानसिक कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है समाज की पारंपरिक सोच। सदियों से महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित रखने की मानसिकता समाज में बनी रही। उन्हें कमजोर, निर्भर और पुरुषों से कम सक्षम माना गया। यह सोच आज भी कई परिवारों में दिखाई देती है। कई स्थानों पर लड़कियों की शिक्षा को आज भी उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना लड़कों की शिक्षा को दिया जाता है। यह असमानता बचपन से ही महिलाओं के आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। दूसरा बड़ा कारण आर्थिक निर्भरता है। जब तक कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होता, तब तक वह अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकता। यही स्थिति महिलाओं के साथ भी रही है। लंबे समय तक महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित रखा गया, जबकि आर्थिक निर्णय पुरुषों के हाथों में रहे। आज भी अनेक महिलाएँ परिवार की आय में योगदान देने के बावजूद आर्थिक निर्णयों में भाग नहीं ले पातीं। इसलिए महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है।शिक्षा महिलाओं के अधिकारों का सबसे मजबूत आधार है। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करती है। एक शिक्षित महिला न केवल स्वयं सशक्त होती है, बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी सशक्त बनाती है। जब महिलाएँ शिक्षित होती हैं, तो वे अपने अधिकारों को समझती हैं और उनके लिए आवाज उठाने का साहस भी रखती हैं। इसलिए महिलाओं की शिक्षा को समाज की प्राथमिकता बनाना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि कोई महिला स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। परिवार महिलाओं के सशक्तिकरण की पहली पाठशाला है। यदि घर में लड़का और लड़की के बीच भेदभाव किया जाएगा, तो समानता की कल्पना अधूरी रह जाएगी। परिवारों को यह समझना होगा कि बेटियाँ भी उतनी ही सक्षम हैं जितने बेटे। उन्हें अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए।सरकार की भूमिका भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। मातृत्व अवकाश, कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, कौशल विकास योजनाएँ और स्वरोजगार के अवसर महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने यह साबित किया है कि अवसर मिलने पर महिलाएँ नेतृत्व की भूमिका सफलतापूर्वक निभा सकती हैं।इन सबके साथ महिलाओं को भी स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। सशक्तिकरण केवल बाहरी अवसरों से नहीं आता, बल्कि भीतर के आत्मविश्वास से भी आता है। महिलाओं को यह समझना होगा कि उनका जीवन केवल दूसरों की सेवा तक सीमित नहीं है। उन्हें अपने सपनों, अपनी पहचान और अपनी क्षमताओं को भी महत्व देना चाहिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता होना है।आज समाज में अनेक महिलाएँ विज्ञान, शिक्षा, खेल, राजनीति, सेना और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही हैं। वे यह साबित कर रही हैं कि अवसर मिलने पर महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। फिर भी ऐसी महिलाओं की संख्या अभी भी अपेक्षाकृत कम है। इसलिए समाज को सामूहिक रूप से यह प्रयास करना होगा कि हर महिला को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। अंततः यह कहा जा सकता है कि समय के साथ महिलाओं के अधिकारों की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास तब तक संभव नहीं है, जब तक उसकी आधी आबादी समान अवसरों से वंचित रहे।ऐसे में आवश्यकता है एक ऐसी विस्तृत और सशक्त व्यवस्था की, जो ज़मीनी स्तर से लेकर देश की सर्वोच्च संस्था संसद तक महिलाओं के अधिकारों को न केवल स्वीकार करे, बल्कि उन्हें समान अवसर भी प्रदान करे।

विश्व मलेरिया दिवस

जयदेव राठी

लेखक एडवोकेट हैं।

मलेरिया मुक्त भारतः सपना या सच?

मलेरिया मामलों में लगभग 80 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। साथ ही, मौतों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। यह सफलता व्यापक स्तर पर चलाए गए जागरूकता अभियानों, मच्छरदानी वितरण, कीटनाशक छिड़काव और समय पर जांच एवं उपचार के कारण संभव हुई है फिर भी, स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं कही जा सकती। दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के कुल मामलों में करीब 73 प्रतिशत का भार भारत पर है। यह इस बात का संकेत है कि देश के कुछ हिस्सों में यह समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है। विशेष रूप से आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित है, मलेरिया का खतरा अधिक रहता है।

हर वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व मलेरिया दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि मानवता के सामने खड़ी उस जिद्दी बीमारी की याद दिलाता है, जिसने सदियों से समाज को कमजोर किया है। मलेरिया आज भी दुनिया के अनेक देशों में मौत और बीमारी का बड़ा कारण बना हुआ है। यह केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि गरीबी, असमानता, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और शासन व्यवस्था से जुड़ा एक जटिल संकट है।

यदि वैश्विक स्थिति पर नजर डालें तो बीते दो दशकों में मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2000 के बाद से दुनिया भर में लगभग 2.2 अरब मामलों और 1.27 करोड़ मौतों को रोका गया है। यह उपलब्धि किसी एक देश की नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वैज्ञानिक प्रगति और जनस्वास्थ्य अभियानों का परिणाम है। लेकिन यह सफलता अब ठहराव की स्थिति में दिखाई दे रही है।

ताजा आंकड़े बताते हैं कि 2023 में विश्वभर में लगभग 26.3 करोड़ मलेरिया के मामले सामने आए, जबकि करीब 5.97 लाख लोगों की मौत इस बीमारी के कारण हुई। इनमें से लगभग 95 प्रतिशत मामले अफ्रीका महाद्वीप में केंद्रित हैं। यह स्थिति इस बात को दर्शाती है कि दुनिया में स्वास्थ्य संसाधनों और सुविधाओं का वितरण अब भी असमान है।

इस ठहराव के पीछे कई गंभीर कारण हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और वर्षा के स्वरूप में बदलाव हो रहा है, जिससे मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। इसके अलावा, मलेरिया परजीवी और मच्छरों में दवाओं तथा कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध विकसित हो रहा है, जिससे उपचार और रोकथाम दोनों कठिन होते जा रहे हैं। कई देशों में आर्थिक संकट, युद्ध और कमजोर स्वास्थ्य ढांचा भी इस बीमारी के खिलाफ प्रयासों को प्रभावित कर रहे हैं।

इतिहास इस विषय में एक महत्वपूर्ण चेतावनी देता है। 1960 के दशक में दुनिया मलेरिया उन्मूलन के काफी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन 1969 में जब वैश्विक प्रयासों में ढील दी गई, तो यह बीमारी फिर से तेजी से फैलने लगी। इस लापरवाही की कीमत लाखों लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। यह अनुभव स्पष्ट करता है कि मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को बीच में छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है।

भारत की भूमिका इस वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजादी के समय, वर्ष 1947 में, भारत में लगभग 7.5 करोड़ मलेरिया के मामले दर्ज किए जाते थे। यह संख्या अब घटकर 2023 में करीब 20 लाख के आसपास रह गई है। यह गिरावट भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों और निरंतर प्रयासों की एक बड़ी सफलता मानी जाती है।

विशेष रूप से पिछले एक दशक में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 2015 से 2023 के बीच मलेरिया मामलों में लगभग 80 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। साथ ही, मौतों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। यह सफलता व्यापक स्तर पर चलाए गए जागरूकता अभियानों, मच्छरदानी वितरण, कीटनाशक छिड़काव और समय पर जांच एवं उपचार के कारण संभव हुई है।

फिर भी, स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं कही जा सकती। दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के कुल मामलों में करीब 73 प्रतिशत का भार भारत पर है। यह इस बात का संकेत है कि देश के कुछ हिस्सों में यह समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है। विशेष रूप से आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित है, मलेरिया का खतरा अधिक रहता है।

भारत सरकार ने मलेरिया नियंत्रण के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई है। 'राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा (2016-2030)' के तहत देश ने 2030 तक मलेरिया मुक्त बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के अंतर्गत उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान, समय पर जांच, प्रभावी उपचार और मच्छरों के नियंत्रण के उपायों को प्राथमिकता दी जा रही है। कई राज्यों और जिलों में इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं, जहां मलेरिया के मामले लगभग समाप्ति की ओर हैं।

वर्तमान समय में मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को और जटिल बनाने वाले कई नए कारक सामने आए हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में असामान्य बदलाव हो रहे हैं, जिससे मच्छरों के पनपने की अवधि और क्षेत्र दोनों बढ़ रहे हैं। शहरीकरण और अनियोजित विकास भी जलभराव और गंदगी को बढ़ावा देते हैं, जो मच्छरों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं।

इसके अलावा, दवाओं के प्रति बढ़ता प्रतिरोध एक गंभीर चिंता का विषय है। यदि यह समस्या और बढ़ती है, तो वर्तमान उपचार पद्धतियां प्रभावहीन हो सकती हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाएगी।

वित्तीय संसाधनों की कमी भी एक बड़ी बाधा बनी हुई है। वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर मलेरिया नियंत्रण के लिए लगभग 4 अरब डॉलर खर्च किए गए, जबकि वास्तविक आवश्यकता करीब 8.3 अरब डॉलर की थी। यह अंतर दर्शाता है कि संसाधनों की कमी के कारण कई योजनाएं पूरी तरह लागू नहीं हो पातीं।

हालांकि, भविष्य के प्रति आशा की किरणें भी दिखाई दे रही हैं। मलेरिया के खिलाफ टीकों का विकास एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे विशेष रूप से बच्चों में होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही, आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी इस लड़ाई को मजबूत बना रहा है।

डिजिटल निगरानी प्रणाली, आंकड़ा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अब मलेरिया के मामलों की पहचान और नियंत्रण अधिक सटीक और तेज हो गया है। इससे समय पर कार्रवाई करना संभव हो रहा है।

विश्व स्तर पर यह समझ भी विकसित हो रही है कि केवल सरकारी प्रयासों से मलेरिया का उन्मूलन संभव नहीं है। इसके लिए समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। स्वच्छता, जल प्रबंधन और व्यक्तिगत सावधानियों को अपनाकर आम नागरिक भी इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारत के लिए 2030 तक मलेरिया मुक्त बनने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंचे, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां जोखिम अधिक है। साथ ही, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से लोगों को इस बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी जाए। अंततः, मलेरिया के खिलाफ यह लड़ाई केवल एक बीमारी को खत्म करने की नहीं, बल्कि एक बेहतर और स्वस्थ समाज के निर्माण की लड़ाई है। यह हमें यह भी सिखाती है कि यदि विज्ञान, नीति और समाज मिलकर काम करें, तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। यदि इतिहास से सबक लिया जाए, वर्तमान की चुनौतियों को समझा जाए और भविष्य के लिए नवाचार को अपनाया जाए, तो वह दिन दूर नहीं जब मलेरिया केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयास, पर्याप्त संसाधन और मजबूत इच्छाशक्ति आवश्यक है। मलेरिया का अंत संभव है–बशर्ते हम इसे प्राथमिकता दें और इस लड़ाई को अंत तक लड़ने का संकल्प बनाए रखें।

हमें इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं किताबें

मुद्दा

डॉ. नरेश गौतम

सहायक प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग, एसआरयू, रायपुर

हम संवेदना से भी दूर होते जा रहे हैं जो मनुष्यता की सबसे बड़ी निशानी है।

विश्व पुस्तक दिवस यानि 23 अप्रैल का पुस्तकों के लिए किसी एक दिन की औपचारिकता होना ही सोचनीय प्रश्न है, बावजूद इसके किताबें जिन्होंने मानव सभ्यता के उस बौद्धिक और सांस्कृतिक आधार को स्मरण करने का मौका देती आयी हैं, जिस पर ज्ञान, विचार और चेतना की पूरी इमारत खड़ी है। पुस्तकें सदियों से मनुष्य की सबसे विश्वसनीय साथी रही हैं। उन्होंने समय, समाज और अनुभवों को सहेजकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुँचाया है। वे केवल शब्दों का संग्रह नहीं रहीं बल्कि उन्होंने अनगिनत सभ्यताओं उनसे जुड़े जीवन को सही दिशा दी है साथ ही दुनिया को एक साझा मंच पर लाने के काम के साथ विविध सभ्यताओं को समझने जानने का मौका दिया है। लेकिन आज का समय एक गहरे विरोधाभास से भरा हुआ है। एक ओर सूचनाओं का भयानक विस्फोट है, तो दूसरी ओर गहन पठन-पाठन और विचारशीलता चिंतन का अभाव। डिजिटल माध्यमों ने ज्ञान को सहज और सुलभ बनाया है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसी के साथ उन्होंने हमारी पढ़ने की आदतों को सतही और अस्थिर भी कर दिया है। मोबाइल स्क्रीन पर निरंतर स्क्रॉल होती खबरें, कुछ सेकंड के वीडियो और त्वरित प्रतिक्रियाओं की संस्कृति ने हमारे धैर्य, एकाग्रता और गहन चिंतन की क्षमता को धीरे-धीरे कमजोर कर दिया है। और वही कारण है कि पुस्तकें हमारे जीवन से धीरे-धीरे ओझल होती जा रही हैं। पढ़ना अब एक स्वाभाविक आदत नहीं, बल्कि एक काम बन गया है। एक ऐसा काम जिसे हम समय मिलने पर करने की सोचते हैं, और वह समय अक्सर कभी आता ही नहीं। लिखना भी अब कई बार केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। विचारों की गहराई कम होती जा रही है, जबकि अभिव्यक्ति का ढाँचा अभी भी पुराने ढर्रे पर टिका हुआ है। तेज़ सूचना के इस युग में भी सार्थक यानि प्राथमिक सूचना और प्रभावी विचारों की कमी होती जा रही है। यह कमी हमें न केवल समाज से, बल्कि अपने ही भीतर के संवाद से भी दूर कर रही है। और यही कारण है कि किताबें केवल अक्षरों, घटनाओं, कल्पनाओं या शोध का संग्रह नहीं होतीं। वे हमारे भीतर के अनुभवों की परतें खोलती हैं। वे हमें सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता प्रदान करती हैं। एक अच्छी पुस्तक हमें प्रश्नों के सामने खड़ा करती है, हमें असहज करती है, और अंततः हमें एक बेहतर मनुष्य बनने की दिशा में प्रेरित करती है। इसके विपरीत, डिजिटल सामग्री अक्सर तात्कालिक संतुष्टि तो देती है, पर स्थायी समझ का निर्माण नहीं कर पाती। कविता और साहित्य हमें बार-बार यह याद दिलाते हैं कि किताबें निर्जीव वस्तुएँ नहीं हैं। वे एक जीवंत संवाद हैं। हमारे और हमारे समय के बीच। वे हमें पुकारती हैं, हमारे भीतर उतरना चाहती हैं, हमें अपने विस्तृत संसार में ले जाना चाहती हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम उस संसार में जाना चाहते हैं? या हमने स्वयं को इतनी सीमित परिधियों में बाँध लिया है कि गहराई से जुड़ने की इच्छा ही समाप्त होती जा रही है? बावजूद इसके तमाम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जिन्होंने समय-समय पर ज्ञान का बाजारीकरण होने से मुक्ति की लड़ाई लड़ी है। ज्ञान सबके लिए सहज और समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। कई डिजिटल मंच हैं जिन्होंने ज्ञान को मुक्त और सर्वसुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन प्रयासों ने यह स्थापित किया है कि ज्ञान किसी एक का स्वामित्व नहीं हो सकता। यह मानवता की साझा धरोहर है। ज्ञान कहीं बाहर से आयातित वस्तु नहीं है। वह हमारे आसपास, हमारे अनुभवों, हमारे समाज और हमारे जीवन में ही निहित है। आवश्यकता केवल उसे देखने, समझने और आत्मसात करने की दृष्टि विकसित करने की है। और इस दृष्टि के निर्माण में पुस्तकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अंततः, जब सब कुछ बदल जाएगा, तब भी एक सच्चाई शेष रहेगी कि किताबें केवल ज्ञान नहीं देतीं, वे हमे असहज करती हैं, वह हमारे भीतर के द्वंद से लड़ने सोचने और आखिर में वे हमें मनुष्य बने रहने के लिए प्रेरित करती हैं!

वक्रोक्ति

अंशु प्रधान

लेखक व्यंग्यकार हैं।

जैसे दिन झालमुड़ी के फिरे वैसे ही सबके फिरें

जैसे दिन झालमुड़ी के फिरे वैसे ही सबके फिरें, ज़िन्दगी के गरमा गर्म भाड़ से निकल के सीधे संसद भवन में जा गिरें। रातों- रात मजदूर वाली फीलिंग से हटके चमाचम स्टार बनें। लोग न सिर्फ आपकी बात करें बल्कि गूगल सर्च करें और कहें हम तो पिछले बीस सालों से झाल मुड़ी के साथ है हमने तो कभी इसका साथ ही नहीं छोड़ा। हमारे तो दादा जी के दादा जी भी सुबह नाश्ते में फिर दोपहर में लंच में और रात को डिनर में सिर्फ झालमुड़ी ही लिया करते थे। वे तो मुड़ी की शक्ल देखे बिना सुबह सोके तक नहीं उठते थे।

जब रातों रात किस्मत चमकती है तब सिर्फ लोगों के दिल ही नहीं बदलते बल्कि बयान तक बदल जाते हैं। एकाएक आप सर्वगुणसम्पन्न और बड़े भले -भले हो जाते हैं। यहां तक कि बड़े लोग अपनी सीट छोड़कर तुरंत आपके लिए उठ खड़े होते हैं जैसे कि बेचारा बंगाली रशोगुल्ला ! बेचारे ने तुरंत अपनी जगह छोड़ दी और तुरंत ही मुड़ी को अपनी गद्दी पर बैठा दिया कि आइए आप विराजिए, कहाँ मैं गोलमटोल बुद्धिहीन और कहाँ आप झार और तीखेपन से युक्त ,जो चटपटा पन आप मे हैं वो भला मुझमे कहाँ ! अब कहीं जाके आपको अपना सही स्थान मिला है। बस ज़िंदगी में भी चटपटे लोग इसी तरह बाजी मार ले जाते हैं और मीठे लोग गोल - गोल घूमते रह जाते हैं।

वैसे देखा जाए तो गरीबों का चना चबेना रईसों

का महंगा शौक हुआ करता है। ये किसी छोटी -मोटी चीज़ का मजाक नहीं है। ये पारस पत्थर वाली बात है जिसे छूकर लोहा भी सोना हो जाता है और फिर कोई नाचीज़ भी अगर किसी रसूकदार आदमी के साथ जुड़ जाए फिर वो चीज़ नाचीज़ नहीं रहती। इस पर भी जब कोई चीज़ प्रधानमंत्री के हाथ को छूकर गुजरे तो फिर उसका सोना हो जाना लाजिमी है। वैसे एक बात तो है हमारे प्रधानमंत्री जी हर सस्ती चीज़ को महंगा बना देते हैं चाहे फिर वो पकौड़े हों या फिर कि बंगाली झालमुड़ी। एकाएक अब बंगाल की झाल मुड़ी, झाल मुड़ी नहीं रही बल्कि अब ये आदरणीय हो गयी है अब ये कोई दस रुपये में मिलने वाली कच्चे तेल की झार से युक्त कोई सस्ती चीज नहीं रही बल्कि महंगी चीज हो गयी है। मैं सोच रही हूं थोड़े ही दिनों में झालमुड़ी के कुछ इस तरह के विज्ञापन न दिखने लग जाएं कहीं जैसे कि 'गजब का स्वाद गजब की मिठास बस एक बार गुजराती झालमुड़ी का स्वाद तो चखिए जनाब।' हो सकता है कल को कोई योग गुरु झालमुड़ी बेचते हुए दिख जाए साथ ही ये भी बताए, 'हमारे यहां की एकदम आयुर्वेदिक झाल मुड़ी खाकर तो देखिए इस से सिर्फ हड्डियां ही मजबूत नहीं बनती बल्कि आपकी त्वचा भी चमकदार बनती है।'

बंगाली सोन्देश,दही मिष्ठी की कतार में किसने सोचा था कि झाल मुड़ी भी शान से आ बैठेगी। ज़िन्दगी में भी अक्सर ऐसा ही होता है आप जिसे सबसे कमजोर मान रहे होते हैं वही अचानक एकदिन आपके बगल से जब चमचमाती कार लेकर गुजरता है तब आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और दिल से एक ही आवाज आती है, 'ये मुंह और मसूर की दाल !' प्रधानमंत्री जी के हाथों में बंगाली सोन्देश भी आ सकता था मगर उसके एलीट होने के नखरे हैं। एलीट होने के भी कोई कम नुकसान थोड़ी हैं। इंसान हो या चीज़ बस वर्ग विशेष की बपौती बनकर रह जाता है। आप क्या जाने की छोटी जगह,छोटे लोग,छोटी सोच से ऊपर दिखने का संघर्ष कितना बड़ा होता है जाने कितने छोटे लोगों को लात मारनी पड़ती है रास्ते से हटाना पड़ता है तब कहीं जाके आदमी बड़ा बनता है। आप क्या सोचते हैं आदमी सिर्फ मेहनत और योग्यता की दम से ऊंचाई तक पहुंचता है।अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आप ज़रूर ही छोटे आदमी हैं यही तो सोच का फर्क है जो सफलता के फर्क में दिखाई देता है। तो फिर सभी लोग झाल मुड़ी खाइये और प्रभु के गुण गाइये।

संदिग्ध परिस्थितियों में थार वाहन से साढ़े पांच लाख का बेग नदारद

सोहागपुर। स्थानीय केनरा बैंक के सामने खड़ी थार वाहन से साढ़े पांच लाख रुपयों से भरा बेग संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने का सनसनीखेज मामला घटित हुआ है। इस मामले की सेमरीहरचंद निवासी तिलक मालवीय ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उक्त बीस वर्षीय तिलक मालवीय सेमरी हरचंद में अनाज व्यापारी पराग शर्मा के यहां मुनीम का काम करता है। बताया जाता है कि मुनीम ने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से साढ़े पांच लाख रुपए निकाले।बाद में अन्य कार्य से केनरा बैंक गया था। लेकिन मुनीम ने जोखिम भरी राशि की थैली अपने पास न रखकर थार वाहन में ही रख दी थी। संयोग से वह थार वाहन को लाक करना भी भूल गया। जब वह केनरा बैंक से वापिस आया तो संदिग्ध परिस्थितियों में पैसों से भरा बैग गायब मिला। घटना की रिपोर्ट के उपरांत पुलिस ने घटनास्थल स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस मामले की गंभीरतापूर्वक जांच में जुटी हुई है।

नगर के अन्दर गड्ढे को छोड़ लोक निर्माण विभाग के फुटपाथ की मरम्मत

सोहागपुर। इस कार्यकाल की नगर पंचायत परिषद कार्यशैली अजीबोगरीब फैसला लेने वाली बन चुकी है कि इस 15 पार्षदों से सुशोभित नगर पंचायत में ऐसा कोई भी पार्षद नहीं हो जो नगर पंचायत परिषद के गलत कार्यों पर टिप्पणी कर सके। जो नियम का हवाला देते हैं ऐसे पार्षदों की सुनवाई नहीं होती है।लगातार की महीनों से स्टेशन बैंक ऑफ इंडिया स्टेशन रोड के सामने मालवीय काम्प्लेक्स को सड़क जिस पर सबसे ज्यादा आवागमन है। यहां कई

सेलून हैं। इसके अलावा आनलाइन दुकानें हैं। जहां प्रतिदिन निरंतर आवागमन होता रहता है। इस सड़क से मुख्य सड़क पर जाने के रास्ते में करीबन आधे फुट के गड्ढे हो चुके हैं। इस व्यस्ततम रास्ते में सड़क का एप्रोच रोड गड्ढों में तब्दील हो चुका है। यहां लगभग प्रतिदिन दो पहिया वाहन सिलिप हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि यह रास्ता सिलोप में बना हुआ है। ऊपर से रास्ता ऊंचा है। जो नीचे की तरफ काफी निचाई वाली सड़क है। जिससे आए दिन वाहन सिलिप हो जाते हैं। पर नगर पंचायत परिषद ने शायद आंखें मूंदकर रखी हुई। बड़े मजे की बात तो यह है कि हाल के दिनों में पलकमती पुल लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है। उसके फुटपाथ की मरम्मत करके वाही वाही लुटी गई। जबकि उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग के अधीन आता है। यदि पलकमती पुल पर चलने वाले नागरिकों एवं वाहनों की इतनी फ़िक्र थी, तो पलकमती पुल के सभी खुल चुके जुआईट को मरम्मत करना था ताकि नागरिकों के वाहनों की टूट-फूट से राहत मिलती। ऐसा लगता है नगर पंचायत परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसा कार्य कर रहे हैं ताकि आगामी नगर निकाय चुनाव मे कांग्रेस की विजय का रास्ता प्रशस्त हो।

आज का किशोर कल का नेतृत्वकर्ता,राष्ट्र को समर्पित किशोर सम्मेलन संपन्न

सोहागपुर। राष्ट्र को समर्पित किशोर सम्मेलन वाटिका ग्रार्डन में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 8से 12 वीं कक्षा के युवाओं को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर किशोर युवाओं को राष्ट्रभक्ति से जोड़ने उनके मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव जगाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किशोर सम्मेलन का आयोजित किया गया था। जिसमें सोहागपुर खंड के विभिन्न ग्रामों के सैकड़ो युवा सम्मेलन में सम्मिलित होकर सम्मेलन में उत्साह,अनुशासन एवं गरिमामय

वातावरण में 3 घंटे तक किशोर सम्मेलन में प्रथम शाखा में विभिन्न तरह के खेल में जिसमें घूमता किला,शेर बकरी,विचित्र छू,यह कश्मीर हमारा है, दंड पकड़ो, खो खो,टैंक युद्ध, गुरु चेला का आयोजन हुआ।इसके पश्चात विभिन्न विषयों पर गटसह चर्चा एवं संवाद हुआ।जिसमें युवाओं को राष्ट्र निर्माण,संस्कार, शिक्षा, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने खेलकूद,अन्य गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सोच है कि आज का किशोर ही कल का नेतृत्वकर्ता है, इसलिए उनमें अच्छे संस्कार, सकारात्मक सोच एवं समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होना अत्यंत आवश्यक है।

देवास में जल गंगा संवर्धन अभियान: बावड़ी सफाई, रैली और जागरूकता से दिया जल संरक्षण का संदेश

देवास। शहर के शीलनाथ धूनी, मल्हार वार्ड क्रमांक 42 में 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के तहत सफाई, निरीक्षण और जनजागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जल संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों को जागरूक किया गया।

मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि घुमन्तु अर्द्ध घुमन्तु परियोजना के अधिकारी अमिताभ श्रीवास्तव (भोपाल) ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद उनका स्वागत किया गया।

अपने उद्बोधन में अमिताभ श्रीवास्तव ने कहा कि समाज में बदलाव के लिए लोगों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें समस्या का हिस्सा नहीं, बल्कि समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। साथ ही जल संरक्षण के महत्व को भी समझाया। कार्यक्रम के दौरान समिति अध्यक्ष हेमंत देवड़ा ने जल मंदिर का अवलोकन करवाया। इसके बाद बावड़ी का निरीक्षण किया गया और सफाई अभियान

चलाया गया। परामर्शदाता सचिन पंचोली ने सभी उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। इसके बाद क्षेत्र में जनजागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को पानी बचाने और स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया गया। नवांकुर संस्था के धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जल को प्रदूषित होने से बचाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखें।

इस कार्यक्रम में वार्ड पार्षद अर्जुन चौधरी, नवांकुर एवं प्रस्फुटन समितियों के सदस्य मौजूद रहे। नगर निगम देवास की सहयोगी संस्था 'टीम फीडबैक फाउंडेशन' से टीम हेड प्रमोद पाठक, टीम लीडर सोहेल पटेल, सुपरवाइजर परवेज पटेल और आईईसी टीम के सदस्य शामिल हुए। जन अभियान परिषद से जिला समन्वयक डॉ. सुप्रती यादव, विकासखंड समन्वयक नीलम सोनी भी उपस्थित रहीं। नव अंकुर संस्था से धर्मेंद्र सिंह राजपूत, दिलीप सिंह, नीलम चौहान मैडम सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इसके अलावा नगर समिति से विमल नागर, कमल सिंह, सुतारखेड़ा से श्याम जी और अन्य समिति सदस्य, परामर्शदाता एवं जिला कार्यालय का स्टाफ भी कार्यक्रम में शामिल हुआ।

बीडीए डीपीआर-डिजाइन तैयार कराएगा, एजेंसियों से प्रस्ताव बुलाए

भोपाल में 3700 एकड़ में बनेगी नॉलेज एंड एआई सिटी

भोपाल (नप्र)। भोपाल के एयरपोर्ट और भौंरी के पास करीब 3700 एकड़ क्षेत्र में नॉलेज एंड एआई सिटी बनेगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिजाइन समेत इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों के लिए एजेंसियों से प्रस्ताव बुलाए हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि नॉलेज एंड एआई सिटी के लिए यह मास्टर प्लान है। इस संबंध में बीडीए ने टेंडर भी जारी किए हैं। ताकि, जल्द ही डीपीआर समेत अन्य कार्य हो सके और फिर नॉलेज एंड एआई सिटी के निर्माण की शुरुआत की जा सके। एक्सपर्ट मनोज मीक ने बताया कि भोपाल में प्रस्तावित नॉलेज एंड एआई सिटी की प्रक्रिया अब अगले प्रशासनिक चरण में प्रवेश कर गई है।

'कमाल का भोपाल' अभियान के तहत लंबे समय से इस विजन को उठा रहे हैं। सरकार ने 13 नवंबर 2025 को औपचारिक गति दी थी। इसके तहत नॉलेज एंड एआई सिटी विकसित करने की घोषणा की गई थी। सिटी के लिए जो ईओआई जारी किया गया है, उनमें शहरी नियोजन, डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अकादमिक संस्थान और कंसोर्टियम्स से भागीदारी आमंत्रित की गई।

मास्टर प्लान के निर्माण में ठोस चरण- कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के अध्यक्ष मीक ने बताया, टेंडर इस बात का संकेत है कि यह एआई सिटी के मास्टर प्लान निर्माण के ठोस चरण में पहुंच चुका है। भौंरी स्थित नॉलेज एंड एआई सिटी के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए सलाहकार चयन के लिए आरएफपी आमंत्रित किया गया है। इससे यह साफ है कि अब प्रोजेक्ट को विजन से आगे बढ़ाकर योजना, सर्वे, व्यवहार्यता, डीपीआर और क्रियान्वयन संरचना की दिशा में ले जाया जा रहा है।

आधुनिक हाईटेक और साइबर सिटी

जानकारी के अनुसार, यह सिटी आधुनिक हाईटेक और साइबर सिटी की तर्ज पर विकसित की जाएगी। इसमें विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान केंद्र और स्टार्टअप्स एक ही जगह स्थापित होंगे। यह सिटी राजाभोज एयरपोर्ट और भौंरी के पास प्रस्तावित है, जहां पहले से आइसर का रिसर्च सेंटर मौजूद है।

नॉलेज एंड एआई सिटी क्या है, क्यों जरूरी है?

नॉलेज एंड एआई सिटी एक आधुनिक स्मार्ट सिटी है, जिसे शिक्षा, अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचार के लिए विकसित किया जाता है। इसमें विश्वस्तरीय संस्थान, स्टार्टअप्स और रिसर्च सेंटर एक साथ काम करते हैं। इसका उद्देश्य तकनीक, ज्ञान और उद्योग को जोड़कर नई संभावनाएं तलाशना है, ताकि नवाचार को बढ़ावा मिले।

देश के कई राज्यों में एआई सिटी

एक्सपर्ट मीक का कहना है कि भोपाल में नॉलेज एंड एआई सिटी की शुरुआत ऐसे समय में हो रही है, जब देश में समान प्रकृति की टेक-आधारित शहरी परियोजनाओं की दौड़ तेज है। कर्नाटक ने बिदादी में एआई-आधारित नई आईटी इंटीग्रेटेड सिटी की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जबकि विशाखापट्टनम में गूगल एआई हब की घोषणा के साथ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर क्षमता, ऊर्जा और फाइबर नेटवर्क को एकीकृत मॉडल में आगे बढ़ाया जा रहा है।

आंध्रप्रदेश की राजधानी अमरावती अब क्वांटम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसी बीच इंडिया एआई मिशन के तहत 38 हजार से अधिक जीपीयू कॉमन कम्प्यूट सुविधा के लिए ऑनबोर्ड किए जा चुके हैं। इसका सीधा अर्थ है कि अब प्रतिस्पर्धा कम्प्यूट, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, टैलेंट और संस्थागत तैयारी की है।

इस प्रोजेक्ट को शिक्षा, शोध, स्टार्टअप, एआई, क्वांटम इंफ्रा, जीसीसी, डेटा और गवर्नेंस-टेक के इंटीग्रेटेड मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट मॉडल के रूप में देखना चाहिए। अब अगला फोकस समयबद्ध सलाहकार चयन, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले, एंकर संस्थानों की पहचान, हरित ऊर्जा, जल सुरक्षा, फाइबर नेटवर्क और मासिक समीक्षा तंत्र पर होना चाहिए।

पति-पत्नी का फांसी लाइव वॉट्सएप स्टेटस देख पुलिस ने दरवाजा तोड़ा

उज्जैन में दंपती को फंदे से उतारा, मां-बाप समेत 12 लोगों के नाम का जिक्र

उज्जैन (नप्र)। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में गुरुवार रात पति-पत्नी व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर फंदे पर झूल गए। सूचना मिलते ही घट्टिया पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी और दोनों को फंदे से उतार लिया। पुलिस टीम ने समय रहते दोनों की जान बचा ली।

जानकारी के मुताबिक, नजरपुर निवासी पति-पत्नी लंबे समय से पारिवारिक विवाद के कारण मानसिक तनाव में थे। परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाने का फैसला किया। आत्महत्या से पहले पति ने व्हाट्सएप स्टेटस में परिवार से परेशान होने की बात लिखी थी, जिसमें मां-बाप समेत 12 लोगों के नाम थे।

व्हाट्सएप स्टेटस से अलर्ट हुई पुलिस, तुरंत पहुंची मौके पर- स्टेटस की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी करण खोवाल ने तुरंत पुलिस टीम को रवाना किया। नजरपुर स्थित घर पहुंचने पर दरवाजा अंदर से बंद मिला। खिड़की से देखा गया कि पति-पत्नी फांसी के फंदे पर झूल रहे थे।

दरवाजा तोड़कर बचाई जान, दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया

थाना प्रभारी ने बाहर से बातचीत कर दोनों का ध्यान भटकाया और टीम को दूसरे रास्ते से अंदर जाने का इशारा किया। इसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों को फंदे से नीचे उतार लिया। उस समय दोनों की सांसें चल रही थीं। पुलिस ने तुरंत उन्हें शासकीय अस्पताल घट्टिया में भर्ती कराया। इलाज के बाद दोनों खतरे से बाहर हैं। होश में आने पर दंपती ने बताया कि वे पारिवारिक विवाद और पिता की प्रताड़ना से परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया।

दूसरी शादी को लेकर विवाद, पिता ने घर से किया था बेदखल

पुलिस जांच में सामने आया कि युवक की दूसरी शादी को लेकर उसके पिता नाराज थे और उसे घर से बेदखल कर दिया था। युवक कई बार अपने हक के लिए पिता से बात करता रहा, लेकिन विवाद बढ़ता गया। अधिकार नहीं मिलने से वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा।

पहली पत्नी से दो बच्चे, दूसरी से नहीं संतान

पुलिस के अनुसार, युवक को पहली पत्नी से दो बच्चे हैं, जबकि रीना से उसकी कोई संतान नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पारिवारिक विवाद के पहलुओं को समझ रही है। थाना प्रभारी करण खोवाल ने दोनों को समझाइश दी और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। पूरी कार्रवाई में उपनिरीक्षक अलकेश डांगे और प्रधान आरक्षक राजेंद्र राठौर की अहम भूमिका रही। टीम की तत्परता से दो जिंदगियां बच सकीं।

गेहूं की पराली जलाने में एमपी देश में नंबर वन

5 साल में 77 हजार से ज्यादा केस, विदिशा-उज्जैन में सबसे ज्यादा मामले

भोपाल (नप्र)। एमपी में गेहूं की पराली जलाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस और आईसीएआर के डेटा के मुताबिक, देश में पराली जलाने के मामलों में एमपी पहले स्थान पर पहुंच गया है। 5 राज्यों के 29,167 मामलों में से करीब 69 प्रतिशत हिस्सेदारी एमपी से ही है। यहां 1-21 अप्रैल के बीच राज्य में 20,164 घटनाएं दर्ज की गईं, जो देश में सबसे अधिक हैं।

जिला स्तर पर देखें तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र विदिशा और उज्जैन गेहूं की पराली जलाने के सबसे आगे है। हालांकि, अभी यह आंकड़ा पिछले साल से थोड़ा कम है।

2025 में कुल 20,422 मामले सामने आए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल फसल अवशेष जलाने के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री का शहर पराली जलाने में टॉप पर- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र विदिशा पराली जलाने में सबसे आगे है। यहां 1-21 अप्रैल तक 2086 घटनाएं सामने आईं। इसके बाद उज्जैन में जहां 2053 और रायसेन में 1982 मामले दर्ज किए गए। वहीं होशंगाबाद में 1705 और सिवनी में 1369 घटनाएं मामले आए।

एमपी के बाद यूपी और हरियाणा में सबसे ज्यादा केस- एमपी के बाद पराली जलाने के मामलों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जहां 1-21 अप्रैल 2026 के बीच 8,889 घटनाएं दर्ज की गईं, हालांकि यह आंकड़ा मध्यप्रदेश से काफी कम है। इसके बाद हरियाणा का स्थान आता है, जहां इस अवधि में 65 मामले सामने आए। वहीं पंजाब में सबसे कम 44 घटनाएं दर्ज की गईं।

किसान पर 3 हजार लोन, सोसाइटी ने लगाया 12,194 ब्याज

किसान बोले- गेहूं बिका नहीं, ऋण कैसे चुकाएं, सरकार की गलती से हुए डिफॉल्टर

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में सहकारिता विभाग के नियम और गेहूं खरीदी की तारीखों में फंसे किसान अब भारी ब्याज के बोझ तले दबने लगे हैं। आलम यह है कि जो किसान समय पर कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी तकनीकी खामियों और नियमों के जाल में उलझाकर चूना लगाया जा रहा है।

भोपाल में कांग्रेस सेवादल के सत्याग्रह में शामिल हुए बैरसिया के ललोई गांव के किसान ओमप्रकाश शर्मा की कहानी इसका बड़ा उदाहरण है।

5 हजार का ब्याज 15 दिनों में 12 हजार लगाया- ओमप्रकाश शर्मा ने अपनी व्यथा बताते हुए दैनिक भास्कर से कहा मैंने ललोई सहकारी समिति बैरसिया से दो लाख रुपए

केसीसी का ऋण लिया था। मुझे कुल 2 लाख 5 हजार रुपए भरने थे। 5 हजार रुपए पहले से ही सोसाइटी में जमा थे। मैंने 2 तारीख को 2 लाख 300 रुपए का चेक मैनेजर को दिया और दस्तावेजों के मुताबिक 24 तारीख को पैसा जमा भी हो गया।सहकारी समिति द्वारा दिए गए पेपर में 4949 रुपए का ब्याज 12194 रुपए लगाया गया है।

खाते में पैसे जमा थे उसके बाद भी ब्याज लगा दिया- ओमप्रकाश ने बताया कि मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं उन 5 हजार रुपयों का वाउचर नहीं भर पाया था, जबकि मेरे पैसे सोसाइटी में जमा थे। लेकिन सोसाइटी ने उस 5 हजार रुपए पर मुझ पर 12,194 रुपए का ब्याज लगा दिया। मैंने 24 मार्च को पैसा जमा किया और मात्र 15 दिनों का इतना बड़ा ब्याज वसूल लिया गया।

9 अप्रैल से खरीदी, 31 मार्च डेडलाइन, किसान बोला- कहां से लाएं पैसा?

ओमप्रकाश ने आगे कहा कि किसान के पास कोई फैक्ट्री या धंधा-बिजनेस तो है नहीं, हमारी आय का एकमात्र साधन खेती है। जब तक फसल बिकेगी नहीं, ऋण कैसे चुकाएंगे? एक तरफ तो हमारा गेहूं तुला नहीं है और दूसरी तरफ सरकार ने 31 मार्च को ऋण वसूली की आखिरी तारीख तय कर दी। किसानों ने जैसे-तैसे दूसरों से कर्ज लेकर लोन चुकाया है, इसके बावजूद समय पर गेहूं खरीदी न होने के कारण प्रदेश के 50 प्रतिशत किसान डिफॉल्टर हो गए हैं। जब फसल की बिक्री ही शुरू नहीं हुई, तो किसान पैसा कहां से लाता? एक तरफ खरीदी शुरू नहीं की और दूसरी तरफ ब्याज लगाकर किसानों को लूटा जा रहा है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मामलों का हो समय सीमा में निराकरण : कलेक्टर

मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई प्रकरण समय-सीमा से बाहर पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध जुर्माना अधिरोपित करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने नामांतरण एवं बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए कम से कम समय-सीमा के भीतर आवेदकों को समाधान उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने तहसील कार्यालय में उपस्थित आवेदकों से चर्चा कर उनकी समस्याएं जानीं तथा कार्यालय में मिल रहे सहयोग के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने आमजन की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए तहसील कार्यालय परिसर में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही परिसर में उपयुक्त स्थान चिन्हित कर सार्वजनिक प्याऊ स्थापित करने के लिए भी कहा। कलेक्टर श्री मिश्रा ने तहसीलदार कोर्ट का निरीक्षण करते हुए निर्देशित किया कि रीडर आईडी पर कोई भी प्रकरण लंबित न रखा जाए तथा नियमित रूप से न्यायालय का संचालन सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर का संवेदनशील पक्ष भी देखने को मिला। उन्होंने तहसील परिसर में बैठे एक छोटे बच्चे को देखकर स्नेहवश अपना वाहन रुकवाया और उसे चॉकलेट दी।

सांदीपनि विद्यालय निरीक्षण

कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने सांदीपनि विद्यालय बनखेड़ी एवं पिपरिया का निरीक्षण कर निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने दोनों विद्यालयों के प्रत्येक खंड का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बनखेड़ी स्थित सांदीपनि विद्यालय के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यालय के नक्शे का अवलोकन किया तथा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ईई पीआईयू को संबंधित निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए तथा बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य किए जाएं। कलेक्टर ने विद्यालय परिसर में खेल मैदान के विकास हेतु आवश्यक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पीआईयू अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्यालय परिसर के चारों ओर अनिवार्य रूप से बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाए तथा सीमांकन कर कॉलम तैयार किए जाएं, जिससे भविष्य में अतिक्रमण की संभावना न रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य सक्षम विभाग के इंजीनियरों से पूरे परिसर का निरीक्षण कराया जाए तथा श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यालय की छात्राओं से संवाद कर उनकी शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर बनाई गई पेंटिंग्स की सराहना करते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन में वृक्षों के महत्व के बारे में जानकारी दी। कलेक्टर ने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने एवं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया तथा स्नेहपूर्वक ट्रॉफियां भी वितरित कीं।

पिपरिया स्थित सांदीपनि विद्यालय के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन समस्त कार्य आगामी 15 जून तक पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि विद्यालय के सभी खंडों में कार्य समानांतर रूप से संचालित किया जाए तथा श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य में तेजी लाई जाए। निर्माण कार्य की धीमी गति पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए संबंधित एजेंसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विद्यालय परिसर में खेल मैदान, पौधारोपण, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, कवर्ड कैंपस, अग्निशमन यंत्र सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण

कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कृषि उपज मंडी बनखेड़ी में संचालित गेहूं एवं चना उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्रों पर उपलब्ध स्कंद की एफएक्यू गुणवत्ता की जांच कराई तथा निर्देश दिए कि उपार्जन कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उपार्जन केंद्रों से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत पर संबंधित उपार्जन समिति द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाए। उन्होंने केंद्रों पर उपस्थित किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और कई मामलों में मौके पर ही समाधान किया। स्लॉट बुकिंग में आ रही तकनीकी समस्या के समाधान हेतु कलेक्टर ने एसडीओ एग्रीकल्चर को निर्देशित किया कि जिला एनआईसी से समन्वय स्थापित कर समस्या का शीघ्र निराकरण कराया जाए। उन्होंने हमालों एवं कांटों (तौल मशीनों) की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए, ताकि किसानों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। कलेक्टर ने किसानों से अपील की कि वे साफ एवं एफएक्यू गुणवत्ता वाले स्कंद ही उपार्जन केंद्रों पर लाएं, जिससे शीघ्रता से खरीदी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने छोटे रकबे वाले शेष किसानों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। मंडी में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने हेतु कलेक्टर ने मंडी सचिव को मंडी रेट बनाए रखने, आवारा पशुओं की समस्या के निराकरण के लिए दो शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने तथा तुलाई के लिए

संक्षिप्त समाचार

अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई-340 पाव गोवा विदेशी मदिरा जब्त, आरोपी गिरफ्तार

विदिशा ,(निप्र)। विदिशा जिले में अवैध मदिरा के धारण, परिवहन, निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी श्री शरद पाठक के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वार्ड नंबर 07, राजपूत कॉलोनी विदिशा में छापामार कार्यवाही की। कार्रवाई के दौरान राजा कुशवाहा पुत्र श्री हर प्रसाद कुशवाहा (उम्र 33 वर्ष), निवासी राजपूत कॉलोनी के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी में मकान से कागज के 7 कार्टूनों में भरी गोवा विदेशी मदिरा की कुल 340 पाव बोतलें बरामद की गईं, जिनकी कुल मात्रा 61.2 बल्क लीटर (ब्लक) पाई गई। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। इसके उपरांत आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जब्त की गई मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 45,900 रुपये आंका गया है। इस संपूर्ण कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक श्री संजय इवने के नेतृत्व में आरक्षक शिवलाल चिडार, पवन गौर, राहुल राठौर, प्रमोद धुर्वे, आशीष कौरव एवं प्रीति परिहार द्वारा संपादित की गई है।

जनगणना प्रशिक्षण का शपथ के साथ समापन-पठारी तहसीलदार ने दिलाई जिम्मेदारी की शपथ

विदिशा ,(निप्र)। विदिशा जिले में जनगणना कार्यों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन गरिमामय वातावरण में शपथ ग्रहण के साथ किया गया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में पठारी तहसीलदार श्री अभिषेक पांडेय द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को शपथ दिलाई गई, जिसे उपस्थित गणनाकारों एवं पर्यवेक्षकों ने एक स्वर में दोहराया। शपथ के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों ने जनगणना कार्य को पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता एवं गोपनीयता के साथ संपन्न करने का संकल्प लिया। इस दौरान उन्हें यह भी समझाया गया कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व है, जिसमें एकत्रित की जाने वाली जानकारी देश की नीतियों एवं योजनाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। कार्यक्रम में प्रशिक्षण के दौरान सिखाए गए विभिन्न तकनीकी एवं व्यवहारिक पहलुओं की पुनरावृत्ति भी की गई। अधिकारियों ने प्रशिक्षणार्थियों को निर्देशित किया कि वे फील्ड में कार्य करते समय पूरी सावधानी बरतें और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। प्रशिक्षित अमला अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ कर जनगणना कार्यों का सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे से आश्वस्त किया गया है

कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशन में उपार्जन समिति की बैठक सम्पन्न

नर्मदापुरम ,(निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन में उपार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें गेहूं खरीदी व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित सभी उपार्जन समिति सदस्यों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि केवल एफएक्यू (स्वच्छ) गुणवत्ता का गेहूं ही खरीदा जाए तथा मिट्टी या अन्य फॉरेन मटेरियल युक्त गेहूं की खरीदी किसी भी स्थिति में न की जाए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने सभी अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का नियमित एवं सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए, ताकि खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी एवं व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि सभी खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए शुद्ध पेयजल एवं छांव की समुचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी उपार्जन प्रक्रिया के तहत पूरी तरह से सतर्क एवं मुस्तैद रहें और किसी भी परिस्थिति पर त्वरित रूप से अपनी प्रतिक्रिया दें। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री हिमांशु जैन, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी आपूर्ति अधिकारी श्रीमती नीता कोरी, उपसंचालक कृषि श्री रविकांत सिंह, एवं जिला उपार्जन समिति के अन्य सदस्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।

वन विभाग द्वारा अब तक 1200 बोल्डर, चेक डैम, ब्रशवुड, चेक डैम, परकोलशन तालाब एवं कंटूर ट्रेंच बनाए

विदिशा ,(निप्र)। जल संरक्षण की दिशा में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत विदिशा जिले के वन क्षेत्रों में भी विभिन्न कार्य जैसे भूजल संवर्धन कार्य, वन्य जीवों के लिए पानी उपलब्ध कराना, तालाब निर्माण, स्टॉप डैम, चैकडेम इत्यादि कार्य किए जा रहे हैं। वन विभाग द्वारा इस अभियान की महत्वता को ध्यानगत रखते हुए अब तक भूजल संवर्धन कार्य, बोल्डर, चेक डैम, ब्रशवुड, चेक डैम, परकोलशन तालाब एवं कंटूर ट्रेंच इत्यादि क्षेत्रों में कार्य करते हुए 2000 लक्ष्य के विरुद्ध 1200 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, जबकि 800 कार्य प्रगति रथ हैं। इसी प्रकार वन क्षेत्र में वन्य जीवों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने तालाबों, सांसर, स्टाप डेम, झिरिया इत्यादि का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसके तहत निर्धारित लक्ष्य 700 के विरुद्ध 500 से अधि की लक्ष्य प्राप्ति की गई है। वन क्षेत्र में पूर्व निर्मित तालाबों का गहरीकरण के लिए भी कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 15 के विरुद्ध सात कार्य पूर्ण करते हुए तालाब गहरीकरण का कार्य किया गया है, जबकि आठ कार्य गहरीकरण के लिए प्रगतिरत हैं। वहीं वर्ष 2026 की वर्षा ऋतु में पौधों के रोपण की तैयारी अंतर्गत 509400 गड्ढे खोदना निर्धारित किया गया था यह लक्ष्य वन विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया गया है।

- कलेक्टर ने पिपरिया-बनखेड़ी क्षेत्र का सघन दौरा कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा
- उपार्जन कार्य में किसानों की समस्याओं पर त्वरित प्रतिक्रिया दे अधिकारी आगामी शैक्षणिक सत्र से पूर्व सांदीपनि विद्यालय पिपरिया को क्रियाशील करने के दिए निर्देश

नर्मदापुरम ,(निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने पिपरिया एवं बनखेड़ी क्षेत्र का सघन दौरा कर तहसील कार्यालय, कृषि उपज मंडी के उपार्जन केंद्रों तथा निर्माणाधीन सांदीपनि विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण, उपार्जन व्यवस्था को सुचारु बनाने एवं विद्यालय निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और तेजी सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री हिमांशु जैन, एसडीएम पिपरिया श्री आकिप खान, तहसीलदार पिपरिया श्री वैभव बैरागी, तहसीलदार बनखेड़ी श्रीमती अंजू लोधी सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने पिपरिया एवं बनखेड़ी क्षेत्र का सघन दौरा कर राजस्व मामलों के निराकरण, कोर्ट संचालन सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने तहसील कार्यालय बनखेड़ी का निरीक्षण कर विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसीलदार बनखेड़ी को निर्देशित किया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त सभी प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए तथा कोई भी प्रकरण समय-सीमा के बाहर न जाए। कलेक्टर श्री

गेहूं उपार्जन केंद्र फरीदपुर में अनियमितता

विदिशा ,(निप्र)। विदिशा जिले के गंजबासौदा तहसील अंतर्गत फरीदपुर स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र में अनियमितताओं के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब हो कि गंजबासौदा के सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा 17 अप्रैल को समिति फरीदपुर, अजय वेयरहाउस अंडिया स्थित उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया गया, जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बासौदा को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार केंद्र पर कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कृषक योगेंद्र रघुवंशी द्वारा शिकायत की गई कि निर्धारित मात्रा से अधिक बारदाने का वजन लिया जा रहा है। जांच के दौरान केंद्र प्रभारी की उपस्थिति में अलग-अलग तौल कांटों से 30 बोरियों का वजन कराया गया, जिसमें से 11 बोरियों का वजन निर्धारित सीमा 580 ग्राम से अधिक पाया गया। इसके अलावा मौके पर समिति का 50 किलोग्राम का बांट नापतौल विभाग से सत्यापित नहीं पाया गया, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह कृत्य रबी उपार्जन नीति 2026-27 की कंडिका 10.3 के विपरीत पाया गया है, जिसे शासन के नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए दंडनीय माना गया है। अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर द्वारा उक्त मामले में समिति प्रबंधक श्री मनोज शर्मा तथा केंद्र प्रभारी श्री राज रघुवंशी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। नोटिस में पूछा गया है कि उनके विरुद्ध पुलिस अभियोजन की कार्रवाई क्यों न की जाए, उन्हें स्थायी रूप से उपार्जन कार्य से पृथक क्यों न किया जाए तथा खरीदी गई अतिरिक्त गेहूं की राशि शासन के पक्ष में राजसात क्यों न की जाए। दोनों संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 30 अप्रैल 2026 को अपर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करें। निर्धारित समय पर संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत न करने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जिला सांख्यिकी अधिकारी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा

विदिशा ,(निप्र)। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में संचालित जनगणना कार्य के अंतर्गत द्वितीय बैच के तीसरे दिन चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण जिला सांख्यिकी अधिकारी श्री सेवाराम रैकवार द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उपस्थित कर्मियों की सहभागिता तथा प्रशिक्षण में दिए जा रहे विषयवस्तु की विस्तृत समीक्षा की।

श्री रैकवार ने प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित गणनाकारों एवं पर्यवेक्षकों से संवाद कर उन्हें जनगणना कार्य की महत्ता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसकी सटीकता और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सभी संबंधित कर्मचारियों को गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण में उपयोग की जा रही सामग्री, डेटा संकलन की प्रक्रिया तथा तकनीकी पहलुओं की भी समीक्षा की

गई। जिला सांख्यिकी अधिकारी ने प्रशिक्षुओं को निर्देशित किया कि वे प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी को व्यवहारिक रूप में लागू करें तथा किसी भी प्रकार की शंका होने पर तुरंत समाधान प्राप्त करें। उन्होंने प्रशिक्षण में अनुशासन बनाए रखने और समयबद्ध तरीके से सभी चरणों को पूर्ण करने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी एवं प्रशिक्षण दल उपस्थित रहा। प्रशासन द्वारा जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु निरंतर मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है, जिससे कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

37 दिन पहले ही नर्मदापुरम जिले ने शत प्रतिशत पूर्ण किया एचपीवी वैक्सीनेशन

नर्मदापुरम ,(निप्र)। स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला नर्मदापुरम ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर प्रदेश स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान के तहत जिले में कुल 11,098 बालिकाओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 फरवरी से प्रारंभ किए गए इस अभियान को जिला प्रशासन ने मिशन मोड में संचालित किया। कलेक्टर श्री सोमेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन ब्लॉक स्तर पर समीक्षा कर मैदानी अमले के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जिले के सभी सात ब्लॉकों–डोलरिया, नर्मदापुरम, बनखेड़ी, पिपरिया, सोहागपुर, माखननगर, सिवनीमालवा सहित केसला एवं इटारसी नगर–ने 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। राज्य स्तर से जिले को 11,096 टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध 11,098 बालिकाओं का टीकाकरण कर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की गई। यह अभियान 28 फरवरी से 21 अप्रैल तक कुल 53 दिनों में पूर्ण किया गया, जबकि निर्धारित अवधि 90 दिनों की थी। इस दौरान जिले में कुल 439 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। ब्लॉकवार उपलब्धि में डोलरिया (1003), नर्मदापुरम (910), बनखेड़ी (1367), पिपरिया (1608), सोहागपुर (1385), माखननगर (1349), सिवनीमालवा (1874), केसला (1135) एवं इटारसी नगर (467) शामिल हैं। डोलरिया ब्लॉक ने सर्वप्रथम 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। अभियान के प्रारंभिक चरण में टीके को लेकर फैली भ्रांतियों और आशंकाओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया। घर-घर संपर्क, सकारात्मक उदाहरणों, वीडियो तथा वैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक किया गया। साथ ही, मीडिया के माध्यम से टीका लगवा चुकी बालिकाओं के अनुभव साझा किए गए, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार टीकाकरण के पश्चात किसी भी बालिका में कोई प्रतिकूल प्रभाव सामने नहीं आया, जिससे अभियान के प्रति जनविश्वास और मजबूत हुआ। राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर बैठकों का आयोजन कर अभियान को सफल बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरसिंह गेहलोत ने इस उपलब्धि के लिए जिला प्रशासन एवं सभी सहयोगी विभागों का आभार व्यक्त किया है। साथ ही मैदानी स्तर पर कार्यरत आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम एवं नर्सिंग स्टाफ के सतत प्रयासों की सराहना की गई है। जिला टीकाकरण अधिकारी एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भी सभी को बधाई एवं धन्यवाद प्रेषित किया गया। अभियान की सफलता में जिला मीडिया प्रभारी श्री सुनील साहू की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने प्रिंट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं तक संदेश पहुंचाया। जिले में एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग सहित समस्त जिला प्रशासन की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित की है। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि यह उपलब्धि सभी विभागों के समन्वित प्रयास, समर्पण और निरंतर मेहनत का परिणाम है।

जल गंगा संवर्धन अभियान में श्रमदान के माध्यम से जूनैयाखेड़ी गांव की प्राचीन चंदन बावड़ी की तस्वीर बदली

विदिशा ,(निप्र)। प्रदेश व्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत विदिशा जिले में जल स्त्रोतों के जीर्णोद्धार का कार्य सतत जारी है। इस अभियान को सफल बनाते हुए जिला प्रशासन द्वारा तीव्र गति से जल स्त्रोतों को संवारने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में जन अभियान परिषद जिला विदिशा द्वारा भी महती भूमिका निभाई जा रही है। इसी क्रम में आज जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत सुरक्षित जल - समृद्ध कल जल स्त्रोत सेवा समागम कार्ययोजना अंतर्गत जल है तो कल है के भाव से जन अभियान परिषद टीम कुरवाई ने चंदन बाबड़ी जुनैयाखेड़ी में श्रमदान कर इस प्राचीन को साफ स्वच्छ करने का कार्य किया है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के आह्वान पर जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड कुरवाई में प्रस्फुटन ग्राम जुनैयाखेड़ी की चंदन बाबड़ी में श्रमदान कर साफ सफाई की गई है।

श्रमदान कार्यक्रम में जिला समन्वयक श्रीमती पूजा श्रीवास्तव, विकासखंड समन्वयक श्री आशीष जैन, नवांकुर संस्था से श्री अर्जुन कुशवाह, मुन्नालाल कुशवाह, श्री मोहर सिंह कुशवाह, श्री बलवीर प्रजापति, परामर्शदाता वर्षा राजपूत, प्रस्फुटन समितियों के सदस्य, सीएमसीएलडीपी के छात्र-छात्राओं एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। प्रातः 9 बजे से प्रारम्भ किया गया श्रमदान दोपहर 12 बजे तक लगातार 3 घंटे चला इस श्रमदान ने चन्दन बाबड़ी की तस्वीर बदल दी है।

कलेक्टर ने सेठानी घाट क्षेत्र का निरीक्षण कर साफ-सफाई, पार्किंग व उचित यातायात प्रबंधन के दिए निर्देश

नर्मदापुरम ,(निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा द्वारा नर्मदापुरम के प्रसिद्ध सेठानी घाट एवं आसपास के क्षेत्रों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने घाट क्षेत्र में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) को निर्देशित किया कि घाट क्षेत्र में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने घाट पहुंच मार्ग एवं घाटों पर भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए की घाटों पर सुगमता से पहुंच के लिए बाजार क्षेत्र में बेहतर यातायात प्रबंधन लागू किए जाने के लिए प्लानिंग करें। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने घाट पहुंच मार्ग पर सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था विकसित करने तथा आवारा पशुओं को गौशाला अथवा कांजी हाउस में स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि घाट क्षेत्र के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित कर व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने सेठानी घाट से लेकर मोरछली चौक तक पैदल भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मार्ग पर संचालित दुकानों को व्यवस्थित रूप से संचालित कराने के निर्देश दिए, ताकि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने निर्देशित किया कि यातायात प्रबंधन के लिए घाट पहुंच मार्ग के समीप प्रमुख चौराहे पर यातायात पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की जाए, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। साथ ही उन्होंने मुख्य मार्गों पर ÷रोको-टोको हेलमेट अभियान÷ प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीएमओ को निर्देश दिए कि राजस्व एवं यातायात विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सभी बिंदुओं पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए तथा उसका शीघ्र क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री जय सोलंकी, सीएमओ श्रीमती हेमेश्वरी पटले, तहसीलदार श्रीमती सरिता मालवीय सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल के भोपाल स्थित निवास में सौजन्य भेंट की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्री श्री पटेल को उनके पुत्र श्री प्रबल पटेल की सगाई की शुभकामनाएं दीं और नवयुगल के उज्जवल भविष्य की कामना की।

दसवीं बोर्ड टॉपर कु. प्रतिभा सोलंकी को प्रोत्साहन स्वरूप मिलेंगे एक लाख रुपये : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने 10वीं बोर्ड में 500 में 499 अंक लाने पर पन्ना की प्रतिभा सिंह को दी बधाई,किया सम्मानित

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दसवीं बोर्ड की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली होनहार छात्रा पन्ना की कु. प्रतिभा सिंह सोलंकी को माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त करने पर एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बेटी कु. प्रतिभा और उनके माता-पिता को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बेटी कु. प्रतिभा को सुशासन की प्रतीक लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर माँ की मूर्ति भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से भेंट तथा आशीर्वाद प्राप्त करने प्रतिभा, परिजन सहित समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) आई थीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतिभा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रतिभा जैसी बेटियां प्रदेश की शान हैं। प्रतिभा की सफलता लाखों बेटियों और अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। बिटिया की उपलब्धि पर पूरे प्रदेश को गर्व है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का कु. प्रतिभा और उनके परिजन ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर अभिवादन किया।

पंचायत राज संस्थाएं लोकतंत्र की सशक्त आधारभूत इकाई : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दीं मंगलकामनाएं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रदेशवासियों को मंगलकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने में पंचायत राज संस्थाएं लोकतंत्र की सशक्त आधारभूत इकाई हैं। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण, स्थानीय स्वशासन, जनभागीदारी, पारदर्शिता, डिजिटल सशक्तिकरण और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में पंचायत राज व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र की होगी जांच

हाईकोर्ट ने छानबीन समिति को 60 दिन में फैसला लेने का ऑर्डर दिया

भोपाल (नप्र)। मप्र की नगरीय प्रशासन राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र विवाद में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सीधे जांच के आदेश देने के बजाय मामले को हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के पास भेजते हुए उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत फैसला करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कमेटी 60 दिन के भीतर प्रमाण पत्र की वैधता पर निर्णय ले। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी।

एससी कांग्रेस के अध्यक्ष ने दायर की है याचिका

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता प्रदीप अहिरवार की शिकायत पर 31 मार्च 2025 को दिए गए आवेदन के आधार पर कमेटी सुनवाई करेगी और संबंधित पक्ष (प्रतिवादी क्रमांक-3) को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से पेश शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि सक्षम प्राधिकारी यानी हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी, यदि पहले निर्णय नहीं लिया गया है तो अब नियमानुसार जांच कर फैसला लेगी और आदेश की सूचना याचिकाकर्ता को देगी।

ग्वालियर में मोटा मुनाफा के लालच में फंसे 40 लोग, दंपती ने दो करोड़ रुपए की ठगी की

ग्वालियर (नप्र)। शहर में एक बड़ा निवेश घोटाला सामने आया है, जहां एक दंपती ने लोगों को हर महीने मोटा मुनाफा देने का लालच देकर करीब दो करोड़ रुपये से अधिक की ठगी को अंजाम दिया। महाराजपुरा इलाके में अजय राठौर और उसकी पत्नी नीतू राठौर ने खुद को एक निवेश कंपनी से जुड़ा बताकर लोगों का विश्वास जीता और धीरे-धीरे दर्जनों लोगों को अपने जाल में फंसा लिया।

अच्छा रिटर्न देकर कायम किया भरोसा – जानकारी के अनुसार, शुरुआत में आरोपियों ने कुछ निवेशकों को समय पर अच्छा रिटर्न देकर भरोसा कायम किया। इसी भरोसे के चलते पीड़ितों ने अपने परिचितों और रिश्तेदारों को भी इस योजना में जोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया और निवेश की रकम लगातार बढ़ती गई।

50 हजार से पांच लाख रुपए तक किए निवेश – ग्वालियर के पीड़ितों का कहना है कि दंपती ने फोनपे, आरटीजीएस और नकद के जरिए पैसे लिए। कई लोगों ने 50 हजार से लेकर 5 लाख रुपये तक निवेश किए। शुरुआती दौर में कुछ लोगों को 10 से 12 हजार रुपये तक मासिक लाभ भी दिया गया, जिससे योजना और विश्वसनीय लगने लगी।

भुगतान देना किया बंद – लेकिन जैसे ही आरोपियों के पास बड़ी रकम जमा हो गई, उन्होंने भुगतान देना बंद कर दिया। जब लोगों ने अपनी मूल राशि वापस मांगी तो टालमटोल शुरू हो गई। कुछ समय बाद दोनों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया और आखिरकार मोबाइल स्विच ऑफ कर शहर से फरार हो गए।

40 से ज्यादा पीड़ितों ने की शिकायत – मामला सामने आने के बाद करीब 40 से ज्यादा पीड़ितों ने पुलिस अधिकारियों को आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कई लोगों के नाम और निवेश की राशि का विस्तृत विवरण भी शामिल किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के बैंक खातों और लेन-देन की जांच में जुटी है और उनकी तलाश के लिए टीम गठित की गई है। अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी और सत्यापन जरूर करें, ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सक्रियता का इंदौर में बड़ा खुलासा होना संभव

हैरी बॉक्सर के करीबी राजपाल को प्रोडक्शन वारंट पर लाए

इंदौर। प्रदेश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सक्रियता को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इंदौर में हाल ही में सामने आए करोड़ों रुपये की फिरौती के मामलों में अब बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्राइम ब्रांच ने गैंग से जुड़े हैरी बॉक्सर के करीबी राजपाल को खरगोन से प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर लाकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल, शहर में बीते दिनों दो अलग-अलग मामलों में दो कारोबारियों से 10 करोड़ और एक उद्योगपति से 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी। इन मामलों की खास बात यह रही कि आरोपियों ने वीपीएन नंबर का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। जांच के दौरान खरगोन में भी इसी तरह की वारदात सामने आने से पुलिस का शक और गहरा गया। इसी कड़ी को जोड़ने और नेटवर्क तक पहुंचने के लिए राजपाल को इंदौर लाया गया है। डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी के अनुसार, आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि फिरौती कॉल्स के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं और इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है।

करोड़ों की फिरौती और धमकियां

इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में गैंग के नाम पर व्यापारियों और बिल्डरों से व्हाट्सअप कॉल के जरिए करोड़ों रुपये (10-15 करोड़ तक) की फिरौती मांगने के मामले सामने आए हैं। हैरी बॉक्सर और राजपाल का कनेक्शन : पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 'हैरी बॉक्सर' के करीबी साथी राजपाल को खरगोन से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया, जिससे गैंग के नेटवर्क का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। पुलिस से बचने के लिए बदमाश वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक संगठित साइबर-अपराध सिंडिकेट की ओर इशारा करता है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, जो भोपाल, इंदौर और खरगोन में गैंग की गतिविधियों की जांच कर रही है। अंतरराज्यीय नेटवर्क-जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क पंजाब और हरियाणा से आगे बढ़कर अब मध्य प्रदेश में भी पैर पसार चुका है, जिसमें विदेशी नंबर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।

एमपी में बाघों के बीच बढ़ते टकराव से बढ़ी वन विभाग की चिंता !

नेशनल पार्कों की क्षमता के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान से मांगी मदद

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश लंबे समय से भारत में बाघों का गढ़ है। यहां बांघों की आबादी 1000 से ज्यादा होने का अनुमान है। मगर अब इनका संरक्षण चुनौती बनता जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के सामने यह सवाल नहीं है कि बाघों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। अब समस्या यह है कि पारिस्थितिक तंत्र को संभाले बिना कितने बाघों को संभाला जा सकता है। कई अभ्यारण अपनी प्राकृतिक सीमाओं के करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए मध्य प्रदेश वन विभाग ने बाघों के आवासों की धारण क्षमता के आकलन के लिए देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान से संपर्क किया है।

जनवरी 2025 से अब तक 79 बाघों की हो चुकी है मौत – वहीं, मध्य प्रदेश में जनवरी 2025 से अब तक लगभग 79 बाघों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर मौतें अपने इलाके को लेकर हुई लड़ाइयों के कारण हुई हैं। मध्य प्रदेश वन विभाग के प्रमुख सुभरंजन सेन ने कहा कि हमने भारतीय वन्यजीव संस्थान से मध्य प्रदेश के बाघ अभ्यारणों के लिए कार्यप्रणाली तैयार करने में मदद करने को कहा है। बाघों की बढ़ती आबादी की वजह से संघर्ष बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ोतरी हुई है। बाघों की ज्यादातर मौतें अपने इलाके में हुई लड़ाइयों के कारण हुई है।

साइंटिफिक मापदड़ों की है जरूरत – वहीं, सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों में इस बात पर जोर दिया है कि यह निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक मानदंडों की तत्काल आवश्यकता है कि प्रत्येक अभ्यारण कितने बाघों को सहारा दे सकता है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि बाघों की संख्या कम होना और बहुत ज्यादा होना, दोनों ही स्थितियों में जोखिम होते हैं।

अभ्यारण की सीमाएं हैं सीमित – विशेषज्ञों का कहना है कि कई अभ्यारण शायद पहले से ही अपने शिकार आधारित सीमाओं के करीब पहुंच रहे हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान के पूर्व डीन वाईवी झाला की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार जहां कुछ अभ्यारण अपनी पूर्व क्षमता के करीब हैं, वहीं अन्य अभ्यारण्यों में अभी भी और बाघों को सहारा देने की गुंजाइश है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया के जरिए कहा...

सप्ताह में 6 दिन होगी गेहूं की खरीदी

100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी सरकार
9 मई तक कर सकेंगे स्लॉट की बुकिंग

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश को संबोधित कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि गेहूं उपार्जन सप्ताह में 6 दिन होगा। शनिवार को अवकाश नहीं होगा। स्लॉट की बुकिंग को 9 मई तक बढ़ा दिया है।सीएम ने कहा कि एमपी में गेहूं खरीद का कोटा 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। अब इसके बाद प्रदेश भर में गेहूं बेचने के लिए परेशान हो रहे मध्यम वर्ग और बड़े किसानों का भी गेहूं उपार्जन हो सकेगा।

सीएम के संबोधन की खास बातें

* सरकार ने किसानों के गेहूं की खरीदी 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन करने का फैसला किया।
*किसानों के लिए खरीदी की स्लॉट खोली जा रही है। किसान अपने अनुसार स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं।
* किसानों से गेहूं खरीदी अब सप्ताह में 6 दिन होगी।
* 30 अप्रैल तक होने वाली स्लॉट बुकिंग को 9 मई तक बढ़ा दिया गया है।

राजगढ़ में इंदौर से आगरा जा रही बस और ट्रक में टक्कर, 29 यात्री हुए घायल, एक की मौत

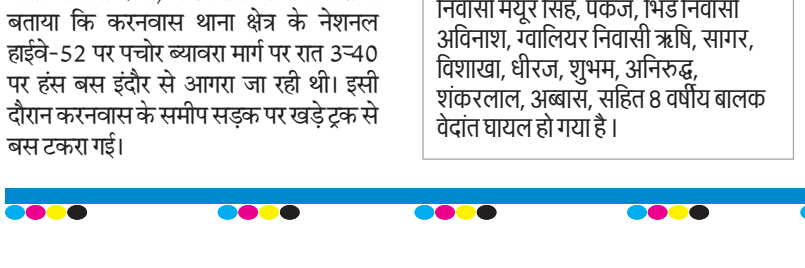

राजगढ़ (नप्र)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के करनवास थाना क्षेत्र में आजाद पेट्रोल पंप के समीप एक ट्रक और बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बस में सवार करीब 29 यात्री घायल हो गए। जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए ब्यावरा सिविल अस्पताल में डायल 108 और 112 की मदद से भर्ती कराया गया। यहां से करीब 24 घायलों को रेफर किया गया। हादसे में एक 35 वर्षीय युवक की भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस इंदौर से आगरा जा रही थी। जब हादसा हुआ तब सभी यात्री नींद में थे।

70 से 80 यात्री थे सवार – वहीं, हादसे के वक्त बस में करीब 70 से 80 यात्री सवार थे। जिसमें से 29 यात्री घायल हो गए। इसके साथ ही बिजिलपूरा थाना दूरसडा जिला दतिया निवासी कल्लू उर्फ परमानंद पिता छक्की लाल राजपूत उम्र 33 वर्ष की मौत हो गई। जिसे पीएम के लिए ब्यावरा सिविल अस्पताल के मोर्चरी रूम में रखा गया। संगीता शर्मा, करनवास थाना प्रभारी ने बताया कि करनवास थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-52 पर पचोर ब्यावरा मार्ग पर रात 3ः40 पर हंस बस इंदौर से आगरा जा रही थी। इसी दौरान करनवास के समीप सड़क पर खड़े ट्रक से बस टकरा गई।

नींद खुली तो मची चीख-पुकार

दरअसल, जब हादसा हुआ तो बस में सवार अधिकतर यात्री नींद में थे। हादसे के दौरान जैसे ही बस टकराई तो बस में सवार यात्रियों की नींद खुली और हादसे को देख चीख-पुकार मच गई। हादसे के बाद सड़क पर कुछ देर तक स्थिति अफरातफरी मच गई। रास्ते से दुर्घटनाग्रस्त बस को क्रेन की मदद से हटाया गया है।

हादसे में ये हुए घायल

इस हादसे में कोल्हापुर निवासी अक्षय, छत्तीसगढ़ निवासी मधुबाला, भिंड निवासी अंकित, मुरैना निवासी किरणशर्मा, सतीश शर्मा, शिवपुरी निवासी गंधर्व सिंह, जलेसर उत्तर प्रदेश निवासी निशांत मित्तल, देवास निवासी सचिन सेन, गोविंदपुरी दिल्ली निवासी सूरज जोशी, अजय जोशी, मथुरा निवासी राजूप्रजापति, बजरंगगढ़ महाराष्ट्र निवासी बलराम, पलानिया निवासी श्री कृष्णा जाटव, मुरैना निवासी आदित्य, दुर्गावती, इंदौर निवासी मयूर सिंह, पंकज, भिंड निवासी अविनाश, ग्वालियर निवासी ऋषि, सागर, विशाखा, धीरज, शुभम, अनिरुद्ध, शंकरलाल, अब्बास, सहित 8 वर्षीय बालक वेदांत घायल हो गया है।

भोपाल में बंटे भाजपा पार्षद के 'लापता' होने के पम्पलेट

लिखा-जो बताएगा उसे 5000 देंगे; परिजन बोले-थाने में शिकायत करेंगे

भोपाल (नप्र)। भोपाल में एक बीजेपी की महिला पार्षद के 'लापता' होने के पम्पलेट्स बंटे हैं। वार्ड-61 की पार्षद मधु शिवनानी की तस्वीर लगे पम्पलेट्स में लिखा कि जो भी पार्षद की जानकारी देगा, उसे 5 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये पम्पलेट्स किसने बंटवाए, इसका खुलासा नहीं हो सका हैॉ मधु शिवनानी पहली बार की पार्षद हैं और उनके पति संजय शिवनानी संगठन में मंडल महामंत्री हैं। वार्ड-61 में अवधपुरी जैसा बड़ा इलाका शामिल हैं। शुक्रवार सुबह पार्षद की तस्वीर लगे पम्पलेट्स वार्ड में अखबारों के अंदर रखे मिलें। जिसमें पार्षद के 3 महीने से लापता होने की बात लिखी गई थी। इनाम की घोषणा के साथ पार्षद की अनुपस्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य कई फर्जी दस्तावेज बनाए जाने की बात भी लिखी गई।

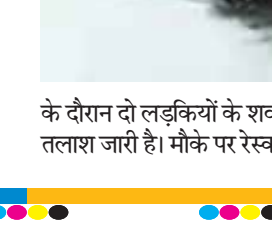

परिजनों को सुबह लगी पम्पलेट्स की जानकारी – इस मामले में मीडिया ने पार्षद के पति संजय शिवनानी से बात की। उन्होंने बताया हमें नहीं पता कि पम्पलेट्स किसने बंटवाए हैं। सुबह हमें मित्रों के माध्यम ये पम्पलेट्स के बारे में जानकारी मिली।

ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से नीदरलैंड से नहीं लौट पाई – बेटा सुशांत नीदरलैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वह बहू के साथ वहीं रहता है। कुछ दिन पहले ही पोते का जन्म हुआ है। इसलिए पत्नी फरवरी में बेटा-बहू के पास नीदरलैंड गई थीं। मार्च में ही वापस आना था, लेकिन ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से फ्लाइड री-शेड्यूल कराना पड़ी। दूसरी ओर, पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। इसलिए डॉ. सुशील कुमार गुप्ता को दिखाया था।

महिला के साथ भागा बेटा तो बंधक बनाकर 70 साल के बुजुर्ग से अमानवीयता

रायसेन (नप्र)। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक महिला के परिवार ने 70 साल के बुजुर्ग को अगवा कर लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की है। आरोप है कि बुजुर्ग के बेटे के साथ वह महिला भाग गई है। घटना पिछले महीने हुई थी। बुधवार को उस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बुजुर्ग को उस वीडियो में शराब की बोतल से पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया है। साथ ही पीटा जा रहा है।

पांच मार्च को महिला को लेकर भागा बेटा – बताया जा रहा है कि बीते पांच मार्च को रायसेन का एक व्यक्ति विदिशा की रहने वाली महिला को लेकर भाग गया। दोनों शादी करने वाले थे। अगले ही दिन आरोपियों ही दिन महिला को भगाने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। 7 मार्च को महिला के परिवार वाले और रिश्तेदार कई गाड़ियों से रायसेन पहुंचे।

रील बना रहीं चार लड़कियां बरगी नहर में बहीं

● दो के शव मिले, तीसरे की तलाश जारी और चौथी बची

जबलपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। शादी समारोह में शामिल होने आईं चार लड़कियां बरगी नहर में बह गई हैं। इनमें से दो का शव बरामद हुआ है। वहीं, तीसरे की तलाश चल रही है। चौथी लड़की तैरकर बाहर निकल आई है। बताया जा रहा है कि रील बनाने के दौरान यह हादसा हुआ है। शादी के घर में मातम का माहौल पसर गया है।

पटेल परिवार में थी शादी – दरअसल, बरगी थाना अंतर्गत सालीवाड़ा निवासी पटेल परिवार के घर में शादी थी। शादी समारोह में लड़कियां आई थीं। इस दौरान बरगी नहर में बह गई हैं। नहर में डूबने की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची।

दो के शव मिले – वहीं, तलाशी अभियान

के दौरान दो लड़कियों के शव मिले हैं। एक की तलाश जारी है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बरगी नहर के पास परिवारजनों की भीड़ मौजूद है। हर जगह चीख पुकार मची है। सालीवाड़ा बरगी स्थित पटेल परिवार के घर आयोजित विवाह समारोह में रिश्तेदार आये थे। बुधवार सुबह शीतल पटेल, सानिया पटेल और तनु पटेल सहित चार लड़कियां नहर में नहाने गई थीं। अतुल मयंक मिश्रा, सीएसपी बरगी

रील बनाने के दौरान हादसा – पुलिस ने बताया कि चारों लड़कियां नहर किनारे मोबाइल फोन से रील बना रही थी। तभी उनका पैर फिसल गया और वह नहर के गहरे पानी में चली गईं। इनमें से एक को तैरना आता था तो वह किसी तरह बाहर निकल गई और तीनों लड़कियां गहरे पानी में बह गईं।

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी – घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी, एसडीआरएफ और होमगार्ड के गोताखोरों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया। तीन घंटे बाद घटनास्थल से आधा किलोमीटर दूर शीतल पटेल और सानिया पटेल के शव बरामद हुए। लापता तनु पटेल के संबंध में कोई सुराग नहीं मिल पाया है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्ट्म के लिए भिजवाकर मर्ग कायम कर प्रकरण को विवेचना में लिया है।